हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 203 बेमेतरा, बुधवार 18 मार्च 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

मुद्रा योजना में एनपीए 2.3 प्रतिशत के करीब

नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को बताया कि मुद्रा योजना में पिछले तीन साल में कुल 15.50 लाख करोड़ रुपये के ऋण दिये गये हैं और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) का अनुपात कुल दिये गये ऋण के 2.3 प्रतिशत के आसपास है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि मुद्रा योजना के तहत मुख्य रूप से तीन श्रेणियां हैं - शिशु, किशोर और तरुण।

रेखा गुप्ता ने भाजपा के नितिन नवीन का किया स्वागत

नयी दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बिहार से राज्यसभा सासंद निर्वाचित होने के उपरांत राट्रीय राजधानी आगमन पर मंगलवार को यहां हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर गुप्ता ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के उच्च सदन में नितिन नवीन की उपस्थिति राष्ट्रहित एवं जनकल्याण के संकल्पों को नई शक्ति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि उनका ध्येयनिष्ठ मार्गदर्शन पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए निरंतर प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है।

दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ा है: डॉ वीरेंद्र

नयी दिल्ली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का आरक्षण और सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण को एक-एक प्रतिशत बढ़ाया है। डॉ कुमार ने लोकसभा में मंगलवार को एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि दिव्यांगों को कौशल विकास योजना से भी जोड़ा गया है और उन्हें रोजगार के लिए सहायता उपलब्ध कराने और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के वितरण की सुविधा भी सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों में आरक्षण को तीन प्रतिशत से बढ़कर पांच प्रतिशत किया गया है।

सरकार ने दो वर्षों में 11 हजार 107 करोड़ की सिंचाई परियोजनाएं की स्वीकृत : 25 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का किया सृजन

मुख्यमंत्री साय के विभागों के लिए 10 हजार 617 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विभागों से संबंधित 10 हजार 617 करोड़ 73 लाख 49 हजार रूपए की अनुदान मांगे विधानसभा में पारित की गई। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 612 करोड़ 29 लाख 20 हजार रूपए, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय 30 करोड़ 92 लाख रूपए, जल संसाधन विभाग के लिए 3 हजार 105 करोड़ 11 लाख 80 हजार रूपए, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय 1145 करोड़ 89 लाख 99 हजार रूपए, विमानन विभाग से संबंधित व्यय 314 करोड़ 99 लाख 90 हजार रूपए, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 416 करोड़ 99 लाख 99 हजार रूपए, सुशासन एवं अभिसरण विभाग से संबंधित व्यय 77 करोड़ रूपए, जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय 469 करोड़ 99 लाख रूपए, ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय 4236 करोड़ 01 लाख 61 हजार रूपए, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय 208 करोड़ 50 लाख रूपए शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अनुदान मांगों की चर्चा के जवाब में कहा कि पिछले दो वर्षों से राज्य सरकार संकल्पित भाव से छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में जुटी है और विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को साकार करने में बजट प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।

राज्य माओवादी हिंसा के अंधकार से बाहर निकल रहा

मुख्यमंत्री साय ने नक्सलवाद के विरुद्ध चल रहे अभियान को लोकतंत्र की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने माओवादी आतंकवाद के अंत का लक्ष्य तय कर उसी दिशा में प्रभावी कार्य किया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास जताया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए उत्सव का क्षण बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन, जवानों की वीरता और प्रदेशवासियों के विश्वास से राज्य माओवादी हिंसा के अंधकार से बाहर निकल रहा है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कहा कि पहले दो बजटों की थीम 'ज्ञान' और 'गति' थी, जबकि इस बार बजट की थीम 'संकल्प' रखी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और डिजिटल गवर्नेंस की नीति अपनाकर व्यवस्थागत लिकेज समाप्त किए हैं, जिसके कारण आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अब सीधे जनकल्याण में खर्च हो रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में आबकारी विभाग का राजस्व 5 हजार 110 करोड़ रुपए था, जो वर्तमान सरकार में बढ़कर 11 हजार करोड़ रुपए अनुमानित है। यह अंतर फर्जीवाड़े पर रोक लगने के कारण आया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में खनिज राजस्व की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 में 12 हजार 305 करोड़ रुपए रहा वहीं वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व बढ़कर 14 हजार 592 करोड़ रुपए हो गया है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 11 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक 17 हजार करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति का अनुमान है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: तीन माह से बड़े बच्चों को गोद लेने वाली महिलाओं को भी मैटरनिटी लीव

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे गोद लेने वाली माताओं के लिए एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि गोद लेने वाली महिलाओं को जन्म देने वाली माताओं के समान ही मातृत्व लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। कोई महिला चाहे कितने भी महीने का बच्चा गोद क्यों न ले, उसे 12 हफ्ते की मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। बता दें कि इसे पहले 2020 की सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 60(4) कहती थी कि केवल तीन महीने से छोटे बच्चों को गोद लेने वाली माताओं को ही 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। अब समझिए अदालत ने क्या कहा? गोद लेने वाली माताओं और जैविक माताओं के बीच अंतर तो है, लेकिन सभी माताओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। परिवार बनाने के गैर-जैविक तरीके (जैसे गोद लेना) भी उतने ही कानूनी हैं जितने जैविक तरीके। गोद लिया बच्चा जैविक बच्चे से अलग नहीं होता। मातृत्व अवकाश एक मूलभूत मानवाधिकार है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि पितृत्व अवकाश को भी सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा बनाया जाए।

पितृत्व अवकाश पर भी कोर्ट की टिप्पणी

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र सरकार पितृत्व अवकाश को भी सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा मानते हुए कानून में शामिल करे। इसका मतलब है कि अब पिता को भी बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी मिल सकेगी। यह फैसला उस याचिका पर आया जिसमें अधिवक्ता हंसानंदिनी नंदूरी ने चुनौती दी थी।

मामला कैसे शुरू हुआ?

कर्नाटक की वकील हंसानंदिनी नंदूरी ने इस प्रावधान को चुनौती दी थी। उन्होंने 2017 में दो बच्चों को गोद लिया था, एक साढ़े चार साल की लड़की और उसका दो साल का भाई। जब उन्होंने अपने नियोक्ता से मातृत्व अवकाश मांगा, तो उन्हें बताया गया कि उन्हें प्रत्येक बच्चे के लिए केवल छह सप्ताह की छुट्टी मिलेगी, क्योंकि बच्चे तीन महीने की उम्र की सीमा पूरी नहीं करते। नंदूरी ने याचिका में कहा कि कानून गोद लेने वाली माताओं और बच्चों के साथ भेदभाव करता है। उन्होंने तर्क दिया कि यह अन्यायपूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक है।

अदालत ने क्या आदेश दिया?

अब गोद लेने वाली माताओं को बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना 12 हफ्ते की मातृत्व अवकाश मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि सभी माताओं के अधिकार समान हैं, चाहे बच्चा जैविक हो या गोद लिया हुआ। अदालत ने केंद्र सरकार को पितृत्व अवकाश को कानून में शामिल करने का भी निर्देश दिया।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात

चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई

नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ-साथ छह राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इन पर्यवेक्षकों में सामान्य, पुलिस और व्यय अधिकारी शामिल हैं। इन्हें चुनाव आयोग के आंख और कान के रूप में वर्णित किया गया है, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जमीनी स्तर पर निगरानी रखेंगे। आयोग के अनुसार सामान्य पर्यवेक्षक की संख्या 557, पुलिस पर्यवेक्षक 188 तथा व्यय पर्यवेक्षक 366 होगी। इनको 832 विधानसभा क्षेत्रों और उपचुनाव वाली सीटों पर तैनात किया जायेगा। आंकड़ों के अनुसार, चुनावी राज्यों में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 294 सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 136, असम और केरल में 51-51, और पुडुचेरी में 17 तथा उपचुनाव वाले राज्यों के लिए आठ सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं।

47 हजार मीट्रिक टन गैस लेकर होर्मुज से भारत लौटा 'नंदा देवी'

नई दिल्ली। जामनगर के वडीनार पोर्ट पर एक बड़ा एलपीजी कार्गो लेकर जहाज एमटी नंदा देवी पहुंचा। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन सुशील कुमार सिंह के अनुसार, जहाज सुबह करीब 2:30 बजे पोर्ट के एंकरिज क्षेत्र में पहुंचा। होर्मुज तनाव के बीच भारत को राहत, भारतीय जहाज शिवालिक 46 हजार टन गैस लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंच। उन्होंने बताया कि नंदा देवी जहाज 46,500 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया है, जिसका ट्रांसफर गहरे समुद्र में शिप-टू-शिप प्रकिया के जरिए किया जाएगा। इस कार्गो को एमटी बीडब्ल्यू बिर्च जहाज में स्थानांतरित किया जाएगा और यह प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। चेयरमैन सुशील कुमार सिंह ने जहाज के कैप्टन और क्रू से मुलाकात कर इस महत्वपूर्ण कार्गो को सुरक्षित पहुंचाने के लिए उनका आभार जताया। साथ ही उन्होंने ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया।

भारत पहुंचने वाला नंदा देवी दूसरा जहाज

एमटी नंदा देवी हाल के दिनों में दूसरा भारतीय एलपीजी जहाज है, जिसने सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर भारतीय तट तक पहुंच बनाई है। इससे ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के प्रयासों को मजबूती मिली है।

हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य क्षेत्र में गश्त की योजनाओं से पीछे हटने पर ट्रंप सहयोगी देशों से नाराज

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों की आलोचना करते हुए कहा है कि हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य मार्ग को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने जिस गठबंधन का प्रस्ताव रखा है, उसके प्रति सहयोगियों में 'उत्साह' की कमी है। हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से ही दुनिया के ऊर्जा संसाधनों के पाँचवें हिस्से की जहाज़ों से जरिये आपूर्ति की जाती है। ट्रंप ने सोमवार देर रात ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही खत्म हो सकता है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस हफ़्ते किसी समाधान की संभावना कम है। उन्होंने इस सैन्य अभियान का बचाव करते हुए कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए यह ज़रूरी था। ट्रंप ने कहा, यह अभियान जल्द ही खत्म हो जाएगा। हमारी दुनिया कहीं ज़्यादा सुरक्षित होगी। गौरतलब है कि ईरान ने 28 फ़रवरी को अमेरिका और इज़रायल द्वारा किए गए हमलों के जवाब में इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी दी थी जिसके बाद फ़ारस की खाड़ी से होने वाली जहाज़ों की आवाजाही काफ़ी हद तक कम हो गई है। ट्रंप ने ब्रिटेन की प्रतिक्रिया पर असंतोष ज़ाहिर करते हुए कहा ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा इस संघर्ष में नाटो को शामिल करने में दिखाई गई हिचकिचाहट से मैं खुश नहीं हैं और बहुत हैरान हूँ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का त्याग और बलिदान देश की अमूल्य धरोहर: मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संस्था के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को 23 मार्च को बेमेतरा जिले में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री साय ने आमंत्रण के लिए संस्था के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान देश के इतिहास में अमूल्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। यह केवल कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को देशभक्ति, समर्पण और राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देने का भी सशक्त माध्यम है।उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में राष्ट्रीय मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं और स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक, संस्था के अध्यक्ष डॉ. शिरीष शर्मा, डॉ. शिवेन्द्र त्रिपाठी, ललित मिश्रा, विनायक दीवान सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक में सभी सदस्यों का मत था कि सदस्य सदन में ऐसा व्यवहार करें

लोकसभा ने आठ सदस्यों का निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया

नयी दिल्ली। लोकसभा ने आठ सदस्यों का निलंबन वापस लेने के प्रस्ताव को मंगलवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिससे उनका निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ध्यानाकर्षण सूचना 374 के खंड दो के तहत वह आठ सदस्यों के निलंबन को वापस लेने का प्रस्ताव रखते हैं। उन्होंने कहा कि निलंबित सदस्यों का निलंबन वापस लिया जाये। इसके बाद प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया है, अत: आठ सदस्यों का निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

इससे पहले कांग्रेस के के. सुरेश ने कहा कि कांग्रेस के सात और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य का निलंबन दुखद है। कल बिरला की अध्यक्षता में हुई बैठक मे इस पर व्यापक चर्चा की गयी। सत्ता और विपक्ष के नेताओं ने अपना-अपना पक्ष रखा। बैठक में सभी सदस्यों का मत था कि सदस्य सदन में ऐसा व्यवहार करें, जिससे एक आदर्श प्रस्तुत हो। कोई भी सदस्य मर्यादा न लांघे। समाजवादी पार्टी के धर्मेन्द्र यादव ने कहा, हम लोग मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, सत्ता पक्ष भी इसी भावना का परिचय दे। तभी सदन सुचारु रूप से चल पायेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की सुप्रिया सुले ने कहा कि नीतियों पर टीका-टिप्पणी की जानी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किसी के लिए कोई टिप्पणी नहीं की जाये। कोई सदस्य लक्ष्मण रेखा पार न करे। ऐसी भावना के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपना व्यवहार सदन में करेंगे, तो सदन अच्छे से चलेगा। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सुले ने लक्ष्मण रेखा पार न करने की बात कही है। कल बैठक में भी इसी तरह की भावना व्यक्त की गयी थी। सदन में महासचिव और अधिकारियों की मेजों पर कोई नहीं चढ़ेगा। जिस तरह का व्यवहार पिछले दिनों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ताली दोनों हाथों से बजती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सदन की गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखेंगे, तो सदन की कार्यवाही अच्छे से संचालित की जा सकेगी। बिरला ने कहा कि सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक में सदन को सुचारु रूप से चलाने देने में सहयोग देने के प्रति प्रतिबद्धता दर्शायी गयी थी। सदन की गौरवशली परम्परा का निर्वाह करने के लिए सभी का सहयोग महत्वपूर्ण है। सदन में और संसद परिसर में सदस्य तख्तियां, फर्जी फोटो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित फोटो नहीं लायेंगे। वह पहले भी कहते रहे हैं।

भारत ने काबुल में अस्पताल पर पाकिस्तान के हमले की कड़ी निंदा की, कहा यह अमानवीय कृत्य

नयी दिल्ली। भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक अस्पताल पर पाकिस्तान के हमले को कायरतापूर्ण और अमानवीय कृत्य बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि भारत सोमवार की रात काबुल के ओमिद नशा मुक्ति अस्पताल पर पाकिस्तान के बर्बर हवाई हमले की कड़ी निंदा करता है। यह हिंसा का एक कायरतापूर्ण और अमानवीय कृत्य है, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों की जान चली गई। इस अस्पताल को किसी भी तरह से सैन्य लक्ष्य नहीं माना जा सकता है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब इस नरसंहार को सैन्य अभियान का नाम देने की कोशिश कर रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा किया गया यह घृणित आक्रमण अफगानिस्तान की संप्रभुता पर एक स्पष्ट हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए सीधा खतरा है।

यह पाकिस्तान के लगातार लापरवाह व्यवहार और अपनी आंतरिक विफलताओं को सीमा पार हिंसा के बढ़ते हिंसक कृत्यों के माध्यम से छिपाने के बार-बार किए जाने वाले प्रयासों को दर्शाता है। बयान में कहा गया है कि यह हमला रमजान के पवित्र महीने के दौरान किया गया, जो दुनिया भर के मुस्लिम समुदायों के लिए शांति, चिंतन और दया का समय होता है, जो इसे और भी निंदनीय बनाता है। ऐसा कोई धर्म, कोई कानून या कोई नैतिकता नहीं है जो किसी अस्पताल और उसके मरीजों को जानबूझकर निशाना बनाने को उचित ठहरा सके।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस आपराधिक कृत्य के दोषियों को जवाबदेह ठहराना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा नागरिकों को निशाना बनाने का यह अंधाधुंध हमला तत्काल बंद हो। जायसवाल ने कहा कि भारत शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है।

कलेक्टर ने जिले की यातायात व्यवस्था, सड़कों की स्थिति और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों की विस्तृत समीक्षा की

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने जिला कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने और जन धन सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दी है । उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना एक गंभीर स्थिति है, जिससे असमय मृत्यु होने और जनधन की अपूरणीय क्षति हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस पर रोक लगाने की दिशा में प्रशासन काफी गंभीर है। उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुधारने और दुर्घटनाओं को कम करने के संबंध में कई कड़ी निर्देश दी है। कलेक्टर ने ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करने , यहां आवश्यक सुरक्षा संकेतक लगाने के साथ ही आवश्यक उपाय करने कहा है।

दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों पर सुरक्षात्मक उपायों पर जोर-कलेक्टर ने जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा में जिले की यातायात व्यवस्था, सड़कों की स्थिति और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बैठक में लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर बार-बार दुर्घटनाएं हो रही हैं (ब्लैक स्पॉट्स), वहां तत्काल सुधारात्मक कार्य किए जाएं। साइन बोर्ड, रंबल स्ट्रिप्स और रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए गए। इसी तरह ?हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता: ,पुलिस और परिवहन विभाग को संयुक्त रूप से अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों और बिना सीट बेल्ट चार पहिया वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।

सड़कों पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करें -कलेक्टर ने ?सड़कों पर अवैध अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई करने कहा। उन्होंने मुख्य मार्गों और चौराहों पर होने वाले अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। ताकि यातायात बाधित न हो और दृश्यता बनी रहे। इसके साथ ही ?स्कूल बसों की जांचः करने ,बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने कहा । कलेक्टर ने सभी स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच करने और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ?आवारा पशुओं का उचित प्रबंधन करने निर्देशित की। कलेक्टर ने सड़कों पर बैठने वाले आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम और संबंधित विभागों को विशेष अभियान चलाने को कहा गया। उन्होंने ?जनजागरूकता पर जोर दिया है। कलेक्टर ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों के पालन से नहीं, बल्कि जागरूकता से भी जुड़ी है-

?कलेक्टर ने अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों के पालन से नहीं, बल्कि जागरूकता से भी जुड़ी है। स्कूलों और कॉलेजों में यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा को लेकर आम नागरिकों के बीच सुरक्षात्मक उपाय के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक यातायात नियमों का पालन करें, सड़क सुरक्षा के लिए अपनी संवेदनशीलता का परिचय देवें।

पत्रकार के खिलाफ दर्ज प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग,एसडीएम जागेश्वर कौशल को सौंपा गया ज्ञापन

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। दक्षिण बस्तर पत्रकार संघ, जिला इकाई बीजापुर द्वारा एसडीएम जागेश्वर कौशल को ज्ञापन सौंपकर पत्रकार रौनक शिवहरे एवं उनके परिवार के खिलाफ दर्ज प्रकरण की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि 6 मार्च को दंतेवाड़ा जिले के गीदम क्षेत्र में निवासरत पत्रकार रौनक शिवहरे के घर के सामने एक ट्रैक्टर चालक द्वारा उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी गई। साथ ही उनके पिता और दो वर्षीय बच्ची को भी ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया, जिसमें वे बाल-बाल बच गए।घटना के बाद पत्रकार द्वारा गीदम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन आरोप है कि थाना प्रभारी ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। उल्टा ट्रैक्टर चालक और उसके साथियों के दबाव में आकर पत्रकार एवं उनके माता-पिता के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया।पत्रकार संघ का कहना है कि बिना समुचित जांच के पत्रकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है।उपलब्ध तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर लगाए गए आरोप प्रथम दृष्ट्या अनुचित प्रतीत होते हैं।इस कार्रवाई से पत्रकार समुदाय में गहरा आक्रोश व्याप्त है और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।संघ ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष न्यायिक जांच कर दोषी अधिकारियों एवं व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन सौंपते समय पत्रकार संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार, सिकसोड पुलिस की त्वरित कार्रवाई

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर /:-कांकेर जिले के थाना सिकसोड क्षेत्र में 17 मार्च 2026 नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी द्वारा 15 मार्च 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें बताया गया कि आरोपी शेरसिंह कोमरा (27 वर्ष), निवासी नेडगांव (थाना भानुप्रतापपुर), ने 12 फरवरी 2026 को नाबालिग को जबरन अपने साथ ले जाकर आमाकोड जंगल के पास एक झोपड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी, जिससे वह भयवश किसी को जानकारी नहीं दे सकी। रिपोर्ट दर्ज होते ही थाना सिकसोड में अपराध क्रमांक 04/2026 के तहत धारा 64(1), 64(2)(एम), 65(1) भारतीय न्याय संहिता एवं 04, 06 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक राखेचा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष बंछोर के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शुभम तिवारी के पर्यवेक्षण में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़कर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया। इसके बाद विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक हेमलता परिहार, सहायक उप निरीक्षक तुमेश्वर साहू, प्रधान आरक्षक धनाजी मौर्य, आरक्षक अनिल तारम, सरजू नेताम एवं दीपा नाग की सराहनीय भूमिका रही।

किसान कल्याण के लिए समर्पित हैं आलोक सिंह ठाकुर : रत्नावली कौशल ने किया भव्य सम्मान

रायपुर/मूक पत्रिका

भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ शासन पूर्व सदस्य रत्नावली कौशल ने भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर पुष्प गुच्छ भेंटकर अभिनंदन किया। एक गरिमामय समारोह में रत्नावली कौशल ने आलोक सिंह ठाकुर जी को लाल गुलाबों का आकर्षक पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर रत्नावली कौशल ने कहा कि आलोक सिंह ठाकुर ने अगस्त 2025 में भाजपा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ का प्रदेशाध्यक्ष पदभार ग्रहण किया था, तब से वे किसान कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। उनके नेतृत्व में मोर्चा ने धान खरीदी में अंतर राशि भुगतान, कृषि बजट में 10,000 करोड़ का ऐतिहासिक प्रावधान एवं गौ धाम योजना जैसे कदमों का सफल प्रचार-प्रसार किया। रत्नावली कौशल ने कहा, ÷आलोक सिंह ठाकुर जी का नेतृत्व किसान मोर्चा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, गौ धाम योजना एवं जैविक खेती को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने में उनका अहम योगदान है।÷रत्नावली कौशल ने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में किसान मोर्चा भाजपा किसान भाइयों के बीच 'विकसित छत्तीसगढ़-विकसित भारत' के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा। समारोह में अन्य पदाधिकारियों ने भी ठाकुर जी का सम्मान किया तथा किसान मोर्चा की संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा की।

न्यायालय कलेक्टर सारंगढ़ में 24 मार्च को उपस्थिति के लिए शिवा साहू को अंतिम अवसर

सारंगढ़ बिलाईगढ़,/मूक पत्रिका

न्यायालय कलेक्टर, जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.)

न्यायालय कलेक्टर सारंगढ़ में शिवा साहू का 24 मार्च को पेशी में उपस्थिति के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने की दशा में न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय में पक्षकार छत्तीसगढ़ शासन बनाम शिवा साहू वगैरह साकिन रायकोना का प्रकरण क्रमांक 202511321300009 लंबित है।

गौधाम संचालन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला बेमेतरा द्वारा गौधाम संचालन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (श्वहढ्ढ) के अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए ईओआई जारी करने की तिथि 23 फरवरी 2026 निर्धारित की गई थी । निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 मार्च 2026, दोपहर 03 बजे तक रखी गई है। इच्छुक संस्थाएँ अपना आवेदन कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ, जिला बेमेतरा (छत्तीसगढ़) में कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक जमा कर सकती हैं। निराश्रित गोवंश के संरक्षण का उद्देश्य गौधाम संचालन का मुख्य उद्देश्य निराश्रित एवं घुमंतू गौवंशीय पशुओं की देखभाल, संरक्षण और सुव्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित करना है। गौधाम में निराश्रित एवं घुमंतू गौवंशीय पशुओं के साथ-साथ गृह विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परीक्षण अधिनियम 2004 (संशोधित 2011) तथा छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण नियम 2014 के अंतर्गत जप्त किए गए गौवंशीय पशुओं को रखा जाएगा। जिला बेमेतरा के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं राज्यकीय राजमार्गों पर स्थित गौठानों में गौधाम की स्थापना की जाएगी, जिससे पशुओं को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जा सके।

चयनित संस्थाओं को मिलेगा संचालन का दायित्व-गौधाम संचालन के लिए पात्र संस्थाओं का चयन किया जाएगा। चयनित संस्था को पशुओं की देखभाल, भोजन-पानी की व्यवस्था, अनुश्रवण, अनुशीलन तथा समुचित प्रबंधन की जिम्मेदारी निभानी होगी। इसके साथ ही मानव संसाधन की व्यवस्था, योजना के क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं निगरानी से संबंधित कार्य भी संस्था द्वारा किए जाएंगे। इच्छुक संस्थाएँ विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ, जिला बेमेतरा से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकती हैं।

किसान हितैषी आलोक सिंह ठाकुर का भव्य सम्मानः दक्ष वैद्य साहू ने अवतरण दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित की

रायपुर/मूक पत्रिका

भाजपा किसान मोर्चा सोशल मीडिया प्रदेश सहप्रभारी एवं हिन्द सेना युवा ब्रिगेड राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्ष वैद्य साहू ने भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर के अवतरण दिवस के शुभ अवसर पर पुष्प गुच्छ भेंटकर अभिनंदन किया। एक गरिमामय समारोह में दक्ष वैद्य साहू ने आलोक सिंह ठाकुर जी को लाल गुलाबों का आकर्षक पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया।भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। दक्ष वैद्य साहू ने कहा कि आलोक सिंह ठाकुर ने अगस्त 2025 में भाजपा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ का प्रदेशाध्यक्ष पदभार ग्रहण किया था, तब से वे किसान कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। उनके नेतृत्व में मोर्चा ने धान खरीदी में अंतर राशि भुगतान, कृषि बजट में 10,000 करोड़ का ऐतिहासिक प्रावधान एवं गौ धाम योजना जैसे कदमों का सफल प्रचार-प्रसार किया। दक्ष वैद्य साहू ने कहा प्रदेशाध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर का नेतृत्व किसान मोर्चा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, गौ धाम योजना एवं जैविक खेती को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने में उनका अहम योगदान है। श्री साहू ने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में किसान मोर्चा भाजपा किसान भाइयों के बीच 'विकसित छत्तीसगढ़-विकसित भारत' के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा। समारोह में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने भी ठाकुर जी का सम्मान किया तथा किसान मोर्चा की संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा की।

नरहरपुर में बड़ी कार्रवाईः ट्रैक्टरों से बैटरी चुराने वाले चोर को पुलिस ने पकड़ा; ब्रेजा कार और 32,000 रु. का सामान जब्त

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर /:-नरहरपुर जिला पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक राखेचा के निर्देशन में नरहरपुर पुलिस ने ट्रैक्टरों से बैटरी और अन्य कीमती सामान चोरी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी चोरी के सामान को अपनी लग्जरी कार में रखकर बेचने की फिराक में घूम रहा था, तभी पुलिस ने उसे घेराबंदी कर धर दबोचा।

क्या है पूरा मामला: ग्राम कोचवाही निवासी प्रार्थी कमल ठाकुर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 मार्च की रात उन्होंने और उनके मामा किशोर जूरी ने अपने-अपने ट्रैक्टर घर की बाड़ी में खड़े किए थे। अगले दिन सुबह देखा तो दोनों ट्रैक्टरों के बैटरी कवर खुले थे और उनमें से कीमती बैटरी, हाइड्रोलिक पट्टी, ट्राली हींज और कल्टीवेटर एडजस्टर गायब थे। चोरी हुए सामान की कुल कीमत करीब 32,000 रुपये बताई गई है।

पुलिस की सक्रियता और गिरफ्तारी: मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सोमेश सिंह बघेल के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी सुखूराम शोरी (45 वर्ष), निवासी बनसागर को हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से निम्नलिखित सामग्रियां बरामद की हैं: दो अलग-अलग कंपनियों की ट्रैक्टर बैटरियां (स्स्न और एमरान)। हाइड्रोलिक पट्टी और ट्राली का अन्य सामान। वारदात में प्रयुक्त वाहनः विटारा ब्रेजा (क्रमांक छत्त 26 श्व 7100) इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी सोमेश सिंह बघेल, प्रधान आरक्षक संवलू राम नेताम, परमानन्द सिन्हा, आरक्षक नीलेश साहू, रमेश नाग, पवन मरकाम और धर्मेंद्र साहू का विशेष योगदान रहा। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है।

मंगलवार और शुक्रवार को आंगनबाड़ी केंद्र एवं स्वास्थ्य केंद्रों में पिलाई जाएगी विटामिन ए और आयरन की सिरप

बेमेतरा जिले में शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ, 17 मार्च से 21 अप्रैल तक चलेगा यह अभियान

बेमेतरा/मूक पत्रिका

स्वास्थ्य विभाग जिला बेमेतरा शिशु संरक्षण माह अर्धवार्षिक विटामिन ए अनुपूरक कार्यक्रम कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशन पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ. अमृत लाल रोहलेडर के मार्गदर्शन में दिनांक 17 मार्च से 21 अप्रैल 2026 तक पूरे एक माह तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को नियमित टीकाकरण दिवस पर आयोजित किया जायेगा। जिसका जिला स्तरीय शुभारंभ आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक-01 वार्ड क्रमांक 14 सिंघौरी, बेमेतरा में आज दिनांक 17 मार्च 2026 को माननीय श्री टाकेश्वर साहू जी, पार्षद, वार्ड क्रमांक-14 एवं श्री प्रकाश ठाकुर जी, पार्षद वार्ड क्रमांक-13, नगर पालिका बेमेतरा के गरिमामयी उपस्थिति में बच्चों को विटामिन-ए सिरप पिलाकर एवं आई.एफए. (आयरन फॉलिक एसिड) की सिरप का वितरण करके किया गया,उक्त अवसर पर डी आई ओ डॉ शरद कोहाड़े स्वयं उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत लाल रोहलेडर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अभियान के दौरान शिशु स्वास्थ्य संवर्धन से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गतिविधियों का सफल संचालन व सेवाओं की प्रदायगी व सुदृढ़ीकरण किया जावेगा। शिशु संरक्षण माह कार्यक्रम के तहत 6 माह से लेकर 05 वर्ष के कुल 96366 बच्चे जिन्हे आयरन सिरप देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसी प्रकार 09 माह से 05 वर्ष तक के कुल 91014 बच्चों को विटामिन ए सिरप की खुराक समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं आंगनबाडी केन्द्रों एवं टीकाकरण सत्र स्थल पर प्रदाय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में उक्त सेवाएं निःशुल्क प्रदाय किया जायेगा जो कि मंगलवार एवं शुक्रवार को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, मितानिनों द्वारा दी जायेगी, अभियान के दौरान गंभीर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन करते हुए उन्हे पोषण पुनर्वास केन्द्र जिला चिकित्सालय बेमेतरा में पोषण आहार की प्रदायगी सहित पूनर्वास हेतु भर्ती किया जायेगा, इसके साथ ही बच्चों का हिमोग्लोबिन जांच, गर्भवती माताओं की जांच एवं बच्चों का टीकाकरण नियमित रूप से किया जायेगा। कलेक्टर महोदया सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के द्वारा सभी जिलेवासीयों को शिशु संरक्षण माह में अपने 6 माह से 5 वर्ष तक आयु के बच्चों को विटामिन 'ए' और आयरन सिरप की खुराक देने और निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं जो कार्यक्रम के दौरान दी जायेगी उनका लाभ लेने हेतु अपील किया गया।

महिला कांग्रेस ने हर्षोल्लास के साथ मनाया होली मिलन समारोह

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला महिला कांग्रेस बेमेतरा द्वारा दुर्ग रोड स्थित सिंघौरी के स्वाद रेस्टोरेंट में होली मिलन समारोह का आयोजन बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से महिला कांग्रेस की बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुईं और आपसी प्रेम, सौहार्द एवं भाईचारे के साथ रंगों के इस पावन पर्व को मनाया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने पर्यावरण एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हर्बल गुलाल से होली खेली। साथ ही पारंपरिक होली गीतों की मधुर धुनों पर महिलाओं ने गीत गाए और नृत्य कर पूरे माहौल को रंगमय बना दिया। उपस्थित महिलाओं ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं। समारोह को रोचक बनाने के लिए कुर्सी दौड़, गीत-संगीत, प्रश्नोत्तरी सहित विभिन्न मनोरंजक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा उपस्थित रहे। उन्होंने सभी महिला कांग्रेस सदस्यों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम के सफल आयोजन की सराहना की। प्रतियोगिताओं में पूर्व पार्षद उषा साहू को फर्स्ट एंट्री पुरस्कार मिला, जबकि चीट उठाओ प्रतियोगिता में ममता चेलक विजेता रहीं। छत्तीसगढ़ी आभूषणों के नाम बताने की प्रतियोगिता में शशि प्रभा गायकवाड़ को विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं ÷क्लीन ऑफ द इवनिंग÷ का खिताब जनपद अध्यक्ष माधुरी रवि परगनिया को दिया गया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीमती रश्मि मिश्रा, जनपद अध्यक्ष माधुरी रवि परगनिया, जिला पंचायत सदस्य शशि प्रभा गायकवाड़, बालकुमारी ध्रुव, शकुन्तला साहू, कांग्रेस महामंत्री रूबी सलूजा, सीमा टिकरिया, जनता साहू, हेमिन यादव, उषा साहू, प्रेमलता मंडावी, विद्या रात्रे सहित बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहीं।

बेमेतरा पुलिस की सख्त कार्रवाई: 95 वाहनों की जांच, 32 चालकों पर चालान

बेमेतरा/मूक पत्रिका

पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू के निर्देशन में बेमेतरा पुलिस द्वारा जिले में अवैध गतिविधियों और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में सघन चेकिंग, फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत ÷सशक्त एप÷ के माध्यम से गुम या चोरी हुए वाहनों की पहचान के लिए 16 मार्च को जिले के विभिन्न थाना और चौक-चौराहों पर कुल 95 वाहनों की जांच की गई। इसमें चौकी मारो क्षेत्र में 10 और यातायात बेमेतरा में 85 वाहनों की चेकिंग शामिल रही। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 32 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कुल 32 प्रकरण दर्ज कर 10,900 रुपये का समन शुल्क वसूला गया। कार्रवाई में बिना सीट बेल्ट, बिना लाइसेंस, वाहन के कागजात प्रस्तुत न करना और खतरनाक तरीके से वाहन खड़ा करने जैसे मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया। पुलिस द्वारा तेज रफ्तार, बिना हेलमेट, तीन सवारी, मॉडिफाइड साइलेंसर और शराब पीकर वाहन चलाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। बेमेतरा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, नाबालिगों को वाहन चलाने न दें, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी

बीजापुर में आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए साक्षरता अभियान का पांचवां बैच शुरू

पुनर्वास केंद्र में 35 लोगों को पढ़ना-लिखना सिखाने की पहल, 22 मार्च को होगी साक्षरता परीक्षा

बीजापुर/मूक पत्रिका

नक्सलवाद छोड़कर मुख्यधारा में लौटे लोगों को नया जीवन देने की कोशिशों के तहत बीजापुर में साक्षरता अभियान का पांचवां बैच शुरू किया गया है। कलेक्टर संबित मिश्रा के मार्गदर्शन में 'उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम' के अंतर्गत यह अभियान पुनर्वास केंद्र में चलाया जा रहा है। इस बार के बैच में 35 ऐसे आत्मसमर्पित लोगों को शामिल किया गया है जो अब तक पढ़ना-लिखना नहीं जानते। प्रशासन का उद्देश्य है कि इन्हें बुनियादी शिक्षा देकर आगे की जिंदगी के लिए तैयार किया जाए। कार्यक्रम के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी लखनलाल धनेलिया समेत शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी शिक्षार्थियों को पढ़ाई के लिए किताबें, कॉपियां और पेन दिए गए, ताकि वे नियमित रूप से अध्ययन कर सकें। अधिकारियों ने बताया कि इस बैच के सभी शिक्षार्थी 22 मार्च को होने वाली साक्षरता परीक्षा में शामिल होंगे। इस मौके पर जिला परियोजना अधिकारी ने स्थानीय गोंड़ी बोली में शिक्षार्थियों से बातचीत की और उन्हें पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के जरिए ही बेहतर और सम्मानजनक जीवन की राह खुलती है।

प्रशासन का मानना है कि ऐसे प्रयासों से आत्मसमर्पित नक्सली धीरे-धीरे समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे और सामान्य जीवन की ओर आगे बढ़ सकेंगे।

हर घटना के बाद उठता सवाल–बरमकेला को कब मिलेगा फायर ब्रिगेड?'

सारंगढ़ बिलाईगढ़ /मूक पत्रिका

नगर पंचायत बरमकेला इन दिनों लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं से दहशत में है। बीते कुछ महीनों में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें दुकानों, घरों और गोदामों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हर घटना के बाद एक ही सवाल उठता है– आखिर कब तक बिना फायर ब्रिगेड के सहारे जूझता रहेगा बरमकेला?

स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग लगने के बाद राहत और बचाव के लिए लोगों को दूसरे शहरों से दमकल वाहन का इंतजार करना पड़ता है। इस देरी के चलते आग विकराल रूप ले लेती है और नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। कई मामलों में स्थानीय लोगों ने खुद पानी और संसाधनों के सहारे आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण स्थिति पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है।

नगरवासियों का कहना है कि अगर समय पर दमकल वाहन उपलब्ध होता, तो कई बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता था। अब यही पीड़ा जनआक्रोश में बदलती नजर आ रही है। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने एकजुट होकर फायर ब्रिगेड वाहन की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर दी है।

अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोहर नायक

अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोहर नायक ने कहा कि ÷नगर में लगातार हो रही आगजनी की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। कई परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हमने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाई है। बरमकेला में फायर ब्रिगेड की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो हम जनहित में बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे।÷

स्थानीय नागरिक बंटी साहू ने कहा

स्थानीय निवासी बंटी साहू ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ÷बरमकेला में बार-बार आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आज तक यहां फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था नहीं है। हर बार हमें दूसरे जगह से गाड़ी आने का इंतजार करना पड़ता है, तब तक सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। आखिर कब तक आम जनता यूं ही नुकसान झेलती रहेगी? प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेकर यहां स्थायी रूप से दमकल वाहन की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि समय पर आग पर काबू पाया जा सके और लोगों की जान-माल की सुरक्षा हो सके।÷

अब देखना यह है कि प्रशासन इस बढ़ते जनआक्रोश को कितनी गंभीरता से लेता है और बरमकेला को कब तक फायर ब्रिगेड जैसी बुनियादी सुविधा मिल पाती है। फिलहाल, हर आगजनी की घटना के साथ जनता का धैर्य जवाब देता जा रहा है और मांग अब आंदोलन का रूप लेती जा रही है।

सारंगढ़ मे झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि, जनजीवन अस्त-व्यस्त

सारंगढ़ /मूक पत्रिका

जिले में अचानक बदले मौसम ने लोगों को हैरान कर दिया। आज दोपहर बाद झमाझम बारिश के साथ तेज ओलावृष्टि ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। करीब एक घंटे से अधिक समय तक लगातार ओले गिरने से सड़कों पर सफेद चादर सी बिछ गई और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। तेज बारिश और ओलों के कारण बाजारों में सन्नाटा छा गया, वहीं राहगीरों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा। कई जगहों पर लोग दुकानों और घरों के छज्जों के नीचे शरण लेते नजर आए। अचानक आई इस मौसम की मार से लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

किसानों पर पड़ी भारी मार

इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है। खेतों में खड़ी प्याज, सब्जी और अन्य फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ओलों की मार से फसलें जमीन पर गिर गईं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है।

घंटों चली ओलावृष्टि

स्थानीय लोगों के अनुसार, ओले काफी बड़े आकार के थे और लगातार गिरते रहे, जिससे खेतों और सड़कों पर मोटी परत जम गई। इससे न सिर्फ खेती को नुकसान हुआ, बल्कि बिजली और यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ा।

गर्मी से मिली राहत

हालांकि इस तेज बारिश और ओलावृष्टि के बीच एक सकारात्मक पहलू भी सामने आया है। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है और मौसम सुहावना हो गया है।

बहरहाल, अचानक बदले मौसम ने जहां एक ओर जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए चिंता बढ़ा दी है। अब सभी की निगाहें शासन-प्रशासन पर टिकी हैं कि उन्हें इस प्राकृतिक आपदा से कितना राहत मिल पाता है।

सारंगढ़ में किसानों की धान खरीदी में कटौती के आरोप पर सरकार का इंकार विधानसभा में उत्तरी जांगड़े ने उठाया सवाल

रायपुर/सारंगढ़/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ विधानसभा में सारंगढ़ क्षेत्र के किसानों की धान खरीदी में कटौती का मुद्दा गूंजा। सारंगढ़ की विधायक श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े ने सहकारिता विभाग से जुड़े इस विषय पर सरकार से सवाल किया और किसानों की धान खरीदी में कथित कटौती तथा टोकन पेंडिंग के संबंध में जवाब मांगा।

विधायक ने प्रश्न के माध्यम से पूछा कि क्या सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारंगढ़ और बरमकेला ब्लॉक के समिति प्रबंधकों को किसानों के धान में कटौती करने, टोकन पेंडिंग रखने और रकबा सरेंडर कराने का निर्देश दिया गया था। यदि ऐसा हुआ तो यह निर्देश किसके आदेश पर दिया गया। इस पर सरकार की ओर से वन मंत्री केदार कश्यप ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई शिकायत या प्रकरण उपस्थित नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में सारंगढ़ में 16,44,165.60 क्विंटल तथा बरमकेला में 13,40,741.20 क्विंटल धान की खरीदी हुई। वहीं वर्ष 2025-26 में सारंगढ़ में 15,63,210.40 क्विंटल और बरमकेला में 13,03,783.20 क्विंटल धान की खरीदी की गई। जो कि पिछले वर्ष कि तुलना में सारंगढ़ विकासखंड में 80955.20 हजार क्विंटल तथा बरमकेला विकासखंड में 36958 हजार क्विंटल कम धान खरीदी से स्पष्ट होता है कि जिले के सहकारिता आयुक्त ने किसानो का हक मारा है। उपरोक्त जवाब से लगता है कि ये अधिकारी लोग क्षेत्र की जनता के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं है सबने देखा और सुना है की जिला के सहकारिता आयुक्त किस तरह से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सारंगढ़ और बरमकेला के समिति प्रबंधक को धमका चमका और दबाव डालकर किसानो का धान नहीं ख़रीदा, फिर भी मंत्री जी जिले के झूठे अधिकारीयों के झूठे जवाब को सही मान लिया और बोलते है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है आयुक्त ने कुछ नहीं बोला बड़े पाक साफ है। इसी प्रकार का झूठ फ्लाई ऐश डंपिंग में बोलते है कि सारंगढ़ में अनुमति ही नहीं फिर भी रोजाना कई डम्फर आकर हमारे क्षेत्र के पानी को प्रदूषित कर दिए है इसका सबूत सारंगढ़ के घरों से निकलता गन्दा पानी और बढ़ते पीलिया के मरीज है। इसी प्रकार का झूठ जल जीवन मिशन में बोलते है पुरे विधानसभा में सभी जगह पानी शुद्ध और पानी की कोई कमी नहीं है सभी गलियों के खोदे गड्ढो को ढलाई कर पाइप लाइन बिछाने का झूठ बोलते है जिले के अधिकारी। सरकार से अस्पताल में डॉक्टर की कमी पूछने पर बोलते है जिले में पर्याप्त डॉक्टर है। इन सभी विभागों झूठे जवाब से मंत्री जी भी खुश और जनता त्रस्त। आखिर इन अधिकारीयों को जिला में संरक्षण देने वाला सरदार कौन है जिसके बदौलत कई अधिकारी अपनी मनमानी और भ्रष्टाचार कर सारंगढ़ की जनता को लूट रहे है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जमीनी स्तर पर किसानों को टोकन और खरीदी से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, किसान महीनों तक पटवारी तहसील कार्यालय का चक्कर लगायेऔर अंतिम में किसानो का पूरा धान नहीं खरीदने से क्षेत्र की किसानो में बहुत आक्रोश है तथा आने वाले समय में जनता की अदालत में फैसला करके किसान विरोधी सरकार को सबक सिखाएंगे।

समय-सीमा बैठक में लंबित प्रकरणों की समीक्षा, लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश

शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने अधिकारियों को जवाबदेही से करना होगा कार्य : कलेक्टर

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष (दिशा भवन) में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी अधिकारियों को जवाबदेही पूर्वक कार्य करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक कसावट लाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन विभागों की प्रगति अपेक्षित स्तर पर नहीं पाई जाएगी, उनके जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि केवल कागजी प्रगति पर्याप्त नहीं है, बल्कि योजनाओं का वास्तविक लाभ धरातल पर दिखना चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, महिला सशक्तिकरण एवं अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि इन योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से फील्ड विजिट कर योजनाओं का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और आवश्यक होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और विकास कार्यों में गति लाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे आमजन से जुड़े मामलों को गंभीरता से लें और समाधान केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएं।

पूर्व बैठक के निर्देशों की भी हुई समीक्षा

बैठक में पूर्व में आयोजित समय-सीमा बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने पाया कि कुछ विभागों में प्रगति संतोषजनक नहीं है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सतत मॉनिटरिंग और समन्वय आवश्यक है। कलेक्टर ने सभी विभागों को लक्ष्य आधारित कार्य योजना तैयार कर समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि जो अधिकारी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहेंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी, विभिन्न विभागों के प्रमुख एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।

अग्निवीर थलसेना हेतु 1 अप्रैल तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

भारतीय थल सेना द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अविवाहित उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर सैनिक के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन पंजीयन व आवेदन आमंत्रित की गई है। भर्ती के लिए इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार 1 अप्रैल 2026 तक थलसेना के वेबसाईट ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन (www.joinindianarmy.nic.in) के माध्यम से ऑनलाईन पंजीयन व आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। अग्निवीर सैनिक भर्ती अंतर्गत जनरल ड्यूटी तकनीकी, ऑफिस असिस्टेंट, ट्रेडमैन, महिला सैन्य पुलिस एवं नियमित कैडर भर्ती, धर्म गुरू, नर्सिंग सहयोगी तथा हवलदार एसएसी के पदों भर्ती की जाएगी। जिसके लिए ऑनलाईन परीक्षा का आयोजन जून 2026 में संभावित है। भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त केन्द्रीय व राज्यकीय शिक्षा बोर्ड व संस्था से कक्षा 8वीं, 10वीं या 12वीं, आटीआई, इंजीनियरिंग डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की ऊंचाई, वजन, सीना विभिन्न पदों हेत अलग-अलग है। अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट हेतु ऑनलाईन परीक्षा के समय टाईपिंग टेस्ट भी देना होगा। उम्मीदवार को चयन हेतु कम्प्यूटर आधारित ऑनलाईन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। भर्ती की विस्तृत जानकारी थल सेना के वेबसाईट सेना भर्ती कार्यालय शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम के पास नवा रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-2965212, 2965214 तथा कार्यालय जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र के अधिकारी रामजीत राम से मोबाइल नंबर 9424184279 से प्राप्त कर सकते हैं ।

संपादकीय

क्या पश्चिम एशिया का युद्ध खत्म कर देगा घर की गैस?

पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से जैसे हालात बन गए हैं और जैसे-जैसे दिन लंबे खिंचते जा रहे हैं, उसके असर का दायरा भी बढ़ने लगा है। युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से जिस तरह की रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, उसके कारण वैसे देश भी बुरी तरह प्रभावित हो हैं, जो टकराव से दूर हैं। दरअसल, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के साझा हमले के बाद समूचा पश्चिम एशिया प्रभावित है और इसका खाड़ी देशों में तेल उत्पादन पर खासा असर पड़ा है।इस बीच ईरान ने जिस तरह होर्मुज जलडमरूमध्य को बाधित कर दिया है, उसके बाद उस मार्ग से होकर दुनिया के कई देशों में तेल की आपूर्ति भी रुक गई है। खासतौर पर भारत में तेल और गैस की दिक्कत जिस रूप में देखी जा रही है, वह कई स्तर पर चिंता पैदा करती है। हालांकि सरकार की ओर से यह कहा गया है कि देश के पास रणनीतिक और व्यावसायिक भंडार की पर्याप्त मात्रा मौजूद है और घरों तथा वाहनों के लिए इसमें कोई कटौती नहीं की गई है।सरकार ने उपभोक्ताओं से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की गैरजरूरी जमाखोरी से बचने की अपील की है। विडंबना यह है कि एक ओर सरकार ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और सुरक्षित बता रही है, दूसरी ओर देश के कई हिस्सों से बाजार में रसोई गैस के लिए अफरा-तफरी की खबरें आ रही हैं। सवाल है कि जब सरकार सब कुछ ठीक होने का आश्वासन दे रही है, जमाखोरी न करने की हिदायत दे रही है, तब भी लोगों के बीच रसोई गैस की कमी होने की आशंका कैसे फैल गई।असल में जब ईरान ने होर्मुज समुद्री मार्ग को रोक दिया और उसका असर तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ने लगा, तब सरकार ने न केवल खाना पकाने के गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी, बल्कि पच्चीस दिन के बाद ही नया सिलेंडर मिलने की शर्त लगा दी। शायद यही वजह है कि लोगों के बीच यह धारणा बनी कि आने वाले दिनों में रसोई गैस की किल्लत होने वाली है।इसी के बाद एहतियातन रसोई गैस के सिलेंडर लेने की एक तरह से होड़ मच गई, जिसका फायदा कालाबाजारी करने वालों ने उठाया और कई जगहों से ऊंची कीमतों पर सिलेंडर बेचे जाने की खबरें आईं। इसी तरह, बिजली से चलने वाले चूल्हों की बिक्री में खासा इजाफा देखा गया। उपजने वाली स्थिति का अनुमान लगाने तथा उसी मुताबिक संकट का सामना करने की तैयारी करने के मामले में सरकार ने उदासीनता क्यों बरती।अब सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम लगाने, जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने की बात कह रही है, लेकिन हकीकत यह है कि रसोई गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर लोग आशंकित हैं।

बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और पश्चिम एशिया के युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को एक बार फिर अस्थिर कर दिया है। तेल और गैस की आपूर्ति से जुड़े समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ने लगा है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव तेज हो गया है। ऐसी स्थिति में भारत जैसे ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भर देश के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है। भारत की आर्थिक गतिविधियां, उद्योग, परिवहन व्यवस्था और आम लोगों का दैनिक जीवन काफी हद तक पेट्रोलियम उत्पादों और गैस पर निर्भर करता है। इसलिए मध्य-पूर्व में किसी भी प्रकार का सैन्य संघर्ष भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सीधे प्रभावित करता है। इस परिस्थिति में भारत सरकार को न केवल ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करनी होगी, बल्कि अफवाहों और बाजार में पैदा होने वाली अनिश्चितता पर भी नियंत्रण रखना होगा। मध्य-पूर्व लंबे समय से दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्रों में शामिल रहा है।

पश्चिम एशिया का संकट-भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी चुनौती?

(जयदेव राठी)

खाड़ी क्षेत्र से दुनिया के अनेक देशों को कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है। इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले किसी भी संघर्ष का सीधा प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अधिक चिंता समुद्री मार्गों को लेकर है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले अधिकांश तेल टैंकर महत्त्वपूर्ण समुद्री रास्तों से होकर गुजरते हैं।

अगर युद्ध के कारण इन मार्गों पर अवरोध उत्पन्न होता है, तो तेल की आपूर्ति में गंभीर बाधा आ सकती है। साथ ही जहाजों की सुरक्षा, बीमा लागत और परिवहन खर्च भी बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव आखिर तेल की कीमतों पर दिखाई देता है। भारत की ऊर्जा संरचना को देखें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था अभी भी बड़े पैमाने पर आयातित तेल और गैस पर निर्भर है। भारत कच्चे तेल की अपनी कुल जरूरत का लगभग अस्सी फीसद से अधिक आयात करता है।

इनमें से एक बड़ा हिस्सा मध्य-पूर्व के देशों से आता है। यही कारण है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ते ही भारत में ऊर्जा बाजार को लेकर चिंता बढ़ जाती है। अगर युद्ध के कारण तेल की आपूर्ति बाधित होती है या कीमतों में तेज वृद्धि होती है तो इसका प्रभाव सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल पेट्रोल और डीजल की कीमतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव होता है। परिवहन महंगा होने से वस्तुओं की ढुलाई की लागत बढ़ती है, जिससे बाजार में कई वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं।

कृषि क्षेत्र भी इससे प्रभावित होता है, क्योंकि खेती से जुड़े कई उपकरण और परिवहन व्यवस्थाएं पेट्रोलियम उत्पादों पर आधारित हैं। इसी तरह, उद्योगों में उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे उत्पादों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। परिणामस्वरूप महंगाई बढ़ने की संभावना बनती है और आम लोगों की क्रय शक्ति पर असर पड़ता है। प्राकृतिक गैस की स्थिति भी भारत के लिए उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। देश के कई उर्वरक संयंत्र, बिजली उत्पादन इकाइयां और औद्योगिक इकाइयां गैस पर निर्भर हैं।

भारत अपनी गैस जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसका बड़ा भाग भी मध्य-पूर्व से आता है। अगर युद्ध के कारण गैस की आपूर्ति प्रभावित होती है, तो उर्वरक और बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। इससे कृषि और उद्योग, दोनों क्षेत्रों पर दबाव बढ़ सकता है। ऊर्जा संकट का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि रणनीतिक चुनौती भी है। ऊर्जा संसाधनों की कमी या कीमतों में अत्यधिक

वृद्धि से किसी भी देश की विकास गति प्रभावित हो सकती है।

भारत जैसे तेजी से विकसित हो रहे देश के लिए ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता बेहद जरूरी है। अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो इससे देश का आयात खर्च बढ़ने के साथ-साथ व्यापार घाटा भी बढ़ सकता है। इसका असर मुद्रा विनिमय दर और वित्तीय संतुलन पर भी पड़ेगा। इन चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाए।

सबसे पहले सरकार को विभिन्न देशों से तेल और गैस की खरीद के विकल्पों को मजबूत करना होगा, ताकि किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता कम की जा सके। इसके साथ ही रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का उपयोग भी संकट के समय महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक तेल भंडार तैयार किए हैं, जिनका उद्देश्य आपात स्थिति में देश की ऊर्जा जरूरतों को कुछ समय तक पूरा करना है। हालांकि केवल भंडार बनाना ही पर्याप्त नहीं है।

सरकार को ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण पर भी ध्यान देना होगा। रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों से ऊर्जा आयात बढ़ाने की दिशा में पहले ही प्रयास किए जा चुके हैं। इस नीति को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में किसी एक क्षेत्र में संकट उत्पन्न होने पर देश की ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित न हो। ऊर्जा संकट की स्थिति में एक और महत्त्वपूर्ण पहलू समाज में फैलने वाली अफवाहें होती हैं। कई बार सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से ऐसी खबरें फैल जाती हैं कि देश में ईंधन की कमी होने वाली है या पेट्रोल-डीजल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ने वाली हैं। ऐसी अफवाहों के कारण लोग घबराहट में ईंधन का अनावश्यक भंडारण करने लगते हैं, जिससे बाजार में कृत्रिम संकट पैदा हो सकता है। इसलिए सरकार और प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि वे समय-समय पर स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी जनता तक पहुंचाते रहें। मीडिया की भूमिका भी इस संदर्भ में अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। ऊर्जा संकट जैसे संवेदनशील विषयों पर अतिरंजना या अपुष्ट जानकारी समाज में अनावश्यक भय और भ्रम पैदा कर सकती है। दीर्घकालिक दृष्टि से देखें तो यह संकट भारत के लिए एक चेतावनी भी है कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में और अधिक प्रयास किए जाएं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के विकास से भविष्य में तेल और गैस पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी काफी संभावनाएं शेष हैं। मध्य-पूर्व का वर्तमान संकट यह स्पष्ट संकेत देता है कि वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष का प्रभाव पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत के लिए यह समय सतर्कता, संतुलन और दूरदर्शिता के साथ नीति बनाने का है। सरकार को ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बाजार में स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। साथ ही अफवाहों और भ्रम की स्थिति से बचने के लिए पारदर्शी सूचना प्रणाली और जिम्मेदार संवाद भी जरूरी है। अगर भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में संयम के साथ कदम उठाता है, तो वह न केवल इस संभावित ऊर्जा संकट से सुरक्षित रह सकता है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी मजबूत आधार तैयार कर सकता है। ऐसी परिस्थितियां कठिन जरूर होती हैं, लेकिन सही नीति और दूरदर्शिता के माध्यम से इन्हें अवसर में भी बदला जा सकता है। यही समय है जब भारत को अपनी ऊर्जा नीति को और अधिक मजबूत, संतुलित और भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाने होंगे।

'कुछ मीठा हो जाए' या 'कुछ बीमार हो जाए'? विज्ञापनों के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई

(प्रभात कुमार)

आहार का स्वाद बनाए रखने के लिए चीनी और नमक बहुत जरूरी है। दुनिया के मशहूर बावर्ची खास और महंगे व्यंजन पकाते हुए नमक की बारी आने पर कहते हैं- स्वादानुसार। नमक तो ज्यादा खाना वैसे भी संभव नहीं होता। मीठा कम खाने के बारे कोई नहीं कहता, इसलिए मीठा रुकने का नाम नहीं लेता।

यह खूब खाया जाता है। इसके असर के बारे में जानते हुए भी लोग इससे बचना जरूरी नहीं समझते। हालांकि मोटापा, मधुमेह और दूसरे कारणों से जब शरीर परेशान होने लगता है, तब मीठा कम करना पड़ता है। हमारी जीवन शैली ही ऐसी है कि चीनी दुखी करने लगे, तब भी किसी न किसी बहाने मीठा खाना छूटता नहीं है।

कितने ही लोग सुबह उठकर गोली खा लेते हैं और दिन में गुलाब जामुन पेश किए जाएं, तो उन्हें मुस्कुराकर स्वीकार कर लेते हैं। कोई खुशखबरी जिंदगी में इठलाती हुई प्रवेश कर जाए और जल्दी से कोई मिठाई न मिल सके, तो चीनी को ही मिठाई मान कर मुंह मीठा करा दिया जाता है। वैसे हर मिठाई में चीनी की ही महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

लगभग हर प्रसाद में मिष्ठान खिलाया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ज्यादा मीठा खाते रहना सेहत के लिए दिन पर दिन खतरनाक हुआ जा रहा है। खुशी मनाने और मनवाने के लिए मुंह मीठा करवाना हमारी ऐतिहासिक परंपरा है और परंपराओं से मुंह मोड़ना हमारे यहां सांस्कृतिक गुस्ताखी मानी जाती है। मीठा खाकर आराम से बैठने के कारण राष्ट्रीय सेहत बिगड़ रही है।

यह पढ़कर और जानकर कसैला अनुभव होता है कि हमारा देश दुनिया की मीठी राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। आशंका है कि वास्तविकता में यह हो भी चुका हो, क्योंकि सच अब बेचारा हो चुका है। पता नहीं वक्त के किस कोने में सिर झुकाए बैठा होगा। 'कुछ मीठा हो जाए' जैसे विज्ञापनों ने प्यार तो बहुत पाया, तभी सामान भी खूब बिकवाया, लेकिन जितना नुकसान मीठा खाते रहने वालों का हुआ, उतना मीठा खाने वाले नहीं समझते।

मिठास के पीछे दुनिया इतनी दीवानी है कि उत्सव और खुशियों की पारंपरिक मिठाई, यानी गुड़ को भी नहीं बख्शा गया। उसे ज्यादा मीठा, कुरकुरा और स्वाद बनाने के लिए उसमें चीनी मिलाना कब से हो रहा है। दर्जनों प्रसिद्ध ब्रांडों की गजक चीनी के सहारे बिक रही है। कितनी ही चीजों में असली चीनी की जगह जो नकली चीनी खिलाई जा रही है, वह असली चीनी से ज्यादा खतरनाक बताई जाती है।

अच्छी सेहत के बारे में समझाने वाले उचित ही कहते हैं कि जब बीमारियां दस्तक देना शुरू कर रही हों तो भोजन में चीनी और नमक कम कर देना चाहिए। इस बारे में वाकई संजीदा विचार करना चाहिए और स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए कोई विज्ञापन प्रेरित करे या न करे, खुद ही अपने आप से कहा जाए कि मीठा ज्यादा नहीं, अब नमकीन भी कम हो जाए। यह दोनों शरीर में कम प्रवेश करेंगे, तो जिंदगी की असली सेहत सलामत रहेगी और तबीयत भी बार-बार खराब होने से बचा करेगी।

यह बिल्कुल सही कहा गया है कि डाक्टर के पास जाकर दवाई खाकर स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहना नहीं है, बल्कि डाक्टर के पास न जाकर, स्वानुशासन अपनाकर स्वस्थ रहना ही वास्तव में स्वस्थ रहना है। यह बात दीगर है कि विषाणु, दुर्घटना, प्रदूषण और गरीबी के पड़ोस में तो कोई भी बीमार हो सकता है। खुशी मनाने के लिए 'कड़वा हो जाए' कहने का प्रचलन भी हमेशा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। मिठाई खाने से ज्यादा स्वाद तो लोग सोमरस पीने और पिलाने में लेते हैं।

यह पेय मिठाई खिलाने से कम रसीला नहीं माना जाता। यही माना जाता है कि खुशी की पार्टी तो तभी पूरी होती है, जब मदिरापान हो। एक बार मिली जिंदगी का पूरा लुत्फ लेने के लिए पीना पिलाना बढ़ रहा है। हमारे देश को इस तरह के स्वाद रस की खपत में दुनिया भर में काफी बढ़त मिली है। खुशी के अवसरों पर बच्चों, युवाओं और महिलाओं से बच बचाकर, 'आज शाम को पार्टी हो जाए' भी खुलकर कहा जा रहा है।

सवालों के घेरे में नीतीश कुमार की विदाई

राजनीति का एक चरित्र है। अपने कदमों को लिए वह जिन कारणों को गिनाती है, हकीकत में वे कारण होते ही नहीं। नीतीश ने भी कहा है कि वे चाहते थे कि संसद के दोनों सदनों और विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य बनें। विधानमंडल और लोकसभा के वे सदस्य रह लिए हैं, लेकिन राज्य सभा के वे सदस्य कभी रहे नहीं। दो दशकों से बिहार की सत्ता की धुरी रहे नीतीश कुमार की विदाई को लेकर सियासी गलियारों में जितनी हैरत जताई जा रही है, सवाल भी उतने ही उठ रहे हैं। बीस साल से कुछ ज्यादा वक्त से लगातार बिहार की सत्ता में बने रहे नीतीश का सियासी स्वभाव ही सवालों और आश्चर्य की वजह बना है। नीतीश ने जब से सत्ता संभाली है, उन्होंने कभी ऐसा जाहिर नहीं किया कि वे सत्ता से दूर हो सकते हैं।

(उमेश चतुर्वेदी)

बीच में जीतन राम मांझी को नौ महीने के लिए सत्ता सौंपकर संन्यासी और बीतरागी जैसा दिखने की कोशिश उन्होंने जरूर की, लेकिन वह सिर्फ दिखावा था। सत्ता का असल सूत्र उनके ही हाथ था। जब लगा कि मांझी उस सूत्र को काट कर स्वाधीन पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस धागे को काट सत्ता खुद थाम ली थी। नीतीश सत्ता को इतनी आसानी से छोड़ देंगे, इस पर आसानी से भरोसा ना करने की वजह उनका अतीत रहा है। कभी जीन विवाद तो कभी किसी दूसरी वजह से उन्होंने अपनी पुरानी सहयोगी बीजेपी को छोड़ उस लालू का हाथ दो-दो बार थाम लिया, जिनके विरोध की बुनियाद पर ही उनकी राजनीति परवान चढ़ी। फिर जब उन्हें लगा कि लालू का साथ उनकी सियासी नैया को डुबो देगा तो फिर बीजेपी की ओर लौटने में भी उन्होंने देर नहीं लगाई। यह सियासी आवाजाही हर हाल में सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की उनकी चाहत का ही प्रतीक लगती है। इसी वजह से उनकी विदाई को सहजता से स्वीकार करना कठिन हो रहा है।

राजनीति का एक चरित्र है। अपने कदमों को लिए वह जिन कारणों को गिनाती है, हकीकत में वे कारण होते ही नहीं। नीतीश ने भी कहा है कि वे चाहते थे कि संसद के दोनों सदनों और विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य बनें। विधानमंडल और लोकसभा के वे सदस्य रह लिए हैं, लेकिन राज्य सभा के वे सदस्य कभी रहे नहीं। इसलिए वे बिहार की राजनीति छोड़ राज्यसभा का सदस्य बनने जा रहे हैं। हो सकता है कि नीतीश की यह चाहत रही हो, लेकिन उनके बिहार को छोड़ने के पीछे का यह सच अधूरा है। विगत दो साल में नीतीश कुमार की जुबान कई बार फिसली है। उनकी हरकतें भी कई बार हास्यास्पद रही हैं। नीतीश की छवि ऐसे गंभीर शख्सियत की रही है, जो नाप-तोलकर बोलता है। इसी छवि ने गाहे-बगाहे फिसलती रही जुबान और उल-जलूल हरकतों के बावजूद उनके प्रति लोगों का सम्मान कम नहीं होने दिया है। इसी छवि के चलते विगत के बिहार चुनाव में एनडीए को भारी जीत भी मिली। लेकिन इसके साथ ही यह भी मान लिया गया कि इन चुनावों के बाद नीतीश की विदाई भी हो सकती है। यह कहना मुश्किल है कि बीजेपी और जनता दल यू ने तय किया हो कि चुनाव बाद नीतीश हट जाएंगे या हटा दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से नीतीश ने खुद को बिहार से दूर किया है, उससे लगता है कि दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच ऐसी समझ विकसित हो चुकी थी। चूंकि इसकी भनक बाहर नहीं लग पाई थी, इसलिए यह बदलाव लोगों को आसानी से पच नहीं रहा।

नीतीश ने जिस जनता दल यू को सींचा-खड़ा किया है, उसका भी चरित्र कुछ-कुछ कांग्रेस की तरह हो गया है। जिस तरह नेहरू-गांधी परिवार कांग्रेस को एक रखने का चुंबक है, नीतीश ही जनता दल यू के लिए उसी तरह के चुंबक हैं। बेशक राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन, संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी, नीतीश के बेहद करीब हैं। लेकिन इन चारों की समूचे जनता दल यू में स्वीकार्यता नहीं है। जदयू को एक नीतीश रख सकते हैं या उनके बेटे निशांत। जदयू को एक रखने के लिए निशांत का राजनीति में आना जरूरी है। राजनीति में उनके प्रवेश की अटकलें करीब दो वर्षों से लगाई जा रही हैं। नीतीश की छवि परिवारवाद विरोधी नेता की भी है। बिहार की राजनीति के केंद्र में उन्हें लाने के पीछे लालू के परिवारवाद पर उनका तीखा हमला भी रहा है। ऐसे में नीतीश के बाद सीधे निशांत की ताजपोशी उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती थी, लिहाजा निशांत को उत्तराधिकार सौंपने के लिए ऐसी राह चुनी गई है, जिससे नीतीश को कम से कम नुकसान हो। इसलिए वे दिल्ली में राज्यसभा की शोभा बढ़ाने जा रहे हैं, जबकि नीतीश बिहार की सत्ता में नंबर दो की पोजिशन संभालने जा रहे हैं। इस कदम से निशांत को सीधे बिहार की सत्ता मिल भी नहीं रही और जदयू पर पकड़ के लिए मजबूत रस्सी भी थमाई जा रही है।

बिहार इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जीविका दीदियों के खाते में अब तक 18 हजार एक सौ करोड़ दिए जा चुके हैं। दो साल में करीब दो लाख

कर्मचारियों की भर्ती के बाद राज्य का वेतन खर्च 70 हजार करोड़ से ज्यादा हो चुका है। पेंशन खर्च पैंतीस हजार करोड़ हो चुका है। राज्य का बजट तीन लाख 67 हजार करोड़ का है। इसमें से पैंसठ फीसद खर्च प्रतिबद्ध खर्च है यानी विकास और योजना पर। राज्य की आर्थिक स्थिति की गड़बड़ी के चलते लालू राज के बाद पहली बार वित्त विभाग को आदेश देना पड़ा है कि कर्मचारियों के वेतन खर्च के अलावा कोई भुगतान ना किया जाए। नीतीश को यह कठिनाई पता है। माना जा रहा है कि बीजेपी को सत्ता सौंपने के पीछे उनका मकसद यह भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राज्य के इस आर्थिक संकट को सत्ता के केंद्र में होने के चलते उसे भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि अपने लोगों के हाथ सत्ता होने के चलते बिहार को मोदी सरकार की ओर से केंद्रीय मदद मिल जाए।

1967 में आठ राज्यों में बनी संविद सरकारों में बीजेपी की पूर्ववर्ती पार्टी जनसंघ ने समाजवादी दलों का साथ दिया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल को छोड़ दें तो हर राज्य में समाजवादी दलों की वह सहयोगी रही। समाजवाद के साथ शुरू बीजेपी की यात्रा में धीरे-धीरे समाजवादी दलों का जनाधार छीजता चला गया। इस तरह उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। बीजेपी की इस वर्चस्ववादी यात्रा की राह में नीतीश का जनता दल यू और नवीन पटनायक का बीजू जनता दल रोड़ा रहा है। उड़ीसा के पिछले चुनाव में बीजेपी पटनायक को पटखनी दे चुकी है और अब नीतीश कुमार ने खुद ही कुर्सी खाली कर दी है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि बिहार में बीजेपी का अगुआ बनने का सपना पूरा होने जा रहा है। नीतीश अब बिहार की सत्ता का अतीत हैं। उनकी उपलब्धियां भी कम नहीं हैं। पहले दो कार्यकाल तक यानी 2015 तक उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। नीतीश की एक और उपलब्धि यह है कि लगातार बीजेपी का साथ होने के बावजूद उन्होंने अपनी सरकार का समाजवादी स्वरूप बचाए रखा। सुशासन और सरकार के समाजवादी स्वरूप के चलते नीतीश की राष्ट्रव्यापी छवि बनी। नीतीश की छवि तो बनी, लेकिन उन्होंने बिहार से बाहर अपना संगठन खड़ा नहीं किया। एक बार अरूणाचल में जदयू के 11 विधायक चुने गए, लेकिन उन्हें सहेजने में नीतीश की दिलचस्पी नहीं रही। इससे दुखी विधायक एक-एक कर पार्टी छोड़ गए। 2023 में इसी छवि के चलते उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस का अहं उनकी राह में आड़े आ गया। अगर कांग्रेस ने अपने नेतृत्व को आगे रखने की चाहत का बलिदान किया होता और नीतीश को संयोजक बना दिया होता, शायद इतिहास अलग होता। लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

25 लाख बनाम 5 लाख : पत्रकार भवन पर संग्राम, 'प्रेस क्लब' नहीं 'पत्रकार सदन' की उठी मांग!

सारंगढ़/मूक पत्रिका

सारंगढ़ जिले में पत्रकारों के भवन निर्माण को लेकर घमासान तेज हो गया है। एक ओर अरुण साव द्वारा अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति को 25 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, वहीं दूसरी ओर प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा द्वारा प्रेस क्लब को 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने जिले के पत्रकारों के बीच असंतोष और आरोप-प्रत्यारोप का माहौल बना दिया है।

अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के सदस्यों ने डिप्टी सीएम का आभार जताते हुए कलेक्टर संजय कन्नौज से भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की मांग की है। उनका स्पष्ट कहना है कि 25 लाख की स्वीकृति राशि का सम्मान करते हुए उन्हें पर्याप्त जमीन दी जानी चाहिए, ताकि एक भव्य पत्रकार भवन का निर्माण हो सके।

वहीं, दूसरी तरफकलेक्टर द्वारा प्रेस क्लब को 5 डिसमिल भूमि आवंटित कर दी गई है, जिसे लेकर विवाद और गहरा गया है। जब इस

विषय पर समिति के जिला अध्यक्ष नरेश चौहान ने कलेक्टर से चर्चा की, तो उनका कहना था कि ÷कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में सिर्फ 5 डिसमिल जमीन देना ही संभव है, जो आवंटित की जा चुकी है।÷इधर, श्रमजीवी पत्रकार संघ ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। संघ के प्रवक्ता मुकेश साहू ने कहा कि भवन किसी एक संगठन के नाम पर नहीं, बल्कि ÷पत्रकार सदन÷ के नाम से बनाया जाना चाहिए, ताकि जिले के सभी पत्रकारों को समान रूप से लाभ मिल सके।उन्होंने यह भी कहा कि चाहे 5 लाख की राशि हो या 25 लाख की स्वीकृति, दोनों ही जनप्रतिनिधियों का सम्मान है, लेकिन भवन का स्वरूप सर्वसमावेशी होना चाहिए। यह किसी एक संगठन का नहीं, बल्कि पूरे पत्रकार समाज का केंद्र बने।

जिला अध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि उनकी समिति लगातार पत्रकार हित में कार्य कर रही है, हर वर्ष बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर उत्कृष्ट पत्रकारों का सम्मान भी किया जाता है। ऐसे में 25 लाख की राशि केवल एक संगठन के लिए नहीं, बल्कि पूरे जिले के पत्रकारों के लिए है।

मामला पहुंचा न्यायालय तक-पत्रकार भवन को लेकर विवाद अब न्यायालय की दहलीज तक पहुंच चुका है। एक ओर 25 लाख की बड़ी स्वीकृति, दूसरी ओर 5 डिसमिल जमीन का सीमित आवंटन–इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनेगा, यह अब प्रशासन और न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा।

अब नजरें कलेक्टर के फैसले पर

पूरे मामले में अब सभी की निगाहें कलेक्टर संजय कन्नौज के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। क्या 25 लाख की राशि के अनुरूप जमीन आवंटित होगी? क्या ÷प्रेस क्लब÷ की जगह ÷पत्रकार सदन÷ बनेगा?

इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तय करेंगे कि सारंगढ़ में पत्रकारों का भविष्य किस दिशा में जाएगा।

इस मौके पर नरेश चौहान जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति, देवराज दीपक कार्यकारी जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति, गोल्डी नायक जिलाध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार संघ, दीपक थवाईत जिलाध्यक्ष प्रेस क्लब व सभी संगठनों के सभी सदस्य मौजूद रहे

राज्य सलाहकार मोनिका सिंह ने की ग्राम पंचायतों में स्वच्छता का निरीक्षण, लोगों को किए जागरूक

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) ग्रामीण के राज्य सलाहकार मोनिका सिंह द्वारा विकासखंड बिलाईगढ़ के विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा कर स्वच्छता से जुड़ी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने ग्रामों में निर्मित पृथक्करण शेड एवं सामुदायिक शौचालयों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मोनिका सिंह ने संबंधित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों से चर्चा करते हुए स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया। एसबीएम राज्य सलाहकार ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए नियमित रूप से कचरा पृथक्करण करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना भी है। इसके लिए जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर स्वच्छता अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।

जगमहंत से महंत सड़क निर्माण में लापरवाही, डामर की जगह ऑयल का उपयोग, घटिया सामग्री से बन रही सड़क

जांजगीर/मूक पत्रिका

ज़िला जांजगीर जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर जगमहंत से महंत प्रधानमंत्री सड़क योजना में गड़बड़ी क्षेत्र में बन रही सड़क के निर्माण कार्य में भारी अनियमितता सामने आ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क निर्माण में डामर की जगह मिल (खराब सामग्री) का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सड़क की गुणवत्ता बेहद खराब हो रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में बहुत ही घटिया किस्म का सामान प्रयोग किया जा रहा है। इससे सड़क जल्दी खराब होने की आशंका है और सरकारी धन का भी दुरुपयोग हो रहा है।

लोगों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराई जाए और दोषी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र में टिकाऊ और अच्छी सड़क बन सके।

कलेक्टर डॉ कन्नौजे द्वारा मिलरों को समय सीमा में धान उठाव को पूर्ण करने के निर्देश

बेमौसम बारिश से धान के नुकसान की रोकथाम हेतु पर्याप्त ढकने के निर्देश

- 20 मार्च को जल संगवारी महाभियान
- जल पखवाड़ा सप्ताह में बनाया जाएगा 10 हजार सोख्ता गड्ढा
- निर्मित भवन को हैंडओवर लेने कलेक्टर का स्वास्थ्य विभाग को निर्देश
- गर्मी के पहले पेयजल विहीन क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था करने के निर्देश

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में जिले के प्रगतिरत विकास कार्यों का समीक्षा किया। उन्होंने जिले के सभी कॉलेज, आईटीआई, हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्राचार्य को निर्देश दिए हैं कि वे सभी युवाओं को अग्निवीर भर्ती में शामिल होने के लिए प्रेरित करें।कलेक्टर ने बेमौसम बारिश से धान के नुकसान की रोकथाम के लिए सहकारिता विभाग के अधीन सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि धान उपार्जन केंद्र में उठाव के लिए बचे धान का रखरखाव प्लास्टिक कवर आदि से ढकने का पर्याप्त व्यवस्था हो। साथ ही सभी राइस मिलरों को समितियो से समय सीमा में धान का उठाव करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बच्चों और नागरिकों के रक्षा के लिए जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी राशन दुकानों को खाली सरकारी भवन या सामुदायिक भवन में संचालित करने के निर्देश दिए, वहीं महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निर्माणाधीन भवनों का मुआयना कर उसके गुणवत्ता को जाँच करने और गर्मी तक पूर्ण करने के लिए संबंधित निर्माण एजेंसी और ठेकेदार को निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने जिले के गर्मी के पहले पेयजल विहीन क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही जल आवर्धन और जल प्रदाय योजना के तहत बरमकेला सरिया में नवीन कनेक्शन शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। जल संरक्षण अंतर्गत जिले में जिला स्तरीय जल संगवारी महा अभियान 20 मार्च को किया जाएगा। जिले के गांव और शहर में लगभग 10 हजार सोख्ता गड्ढा का निर्माण किया जाएगा। डॉ संजय कन्नौजे ने स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियो को उनके विभाग के लिए निर्मित भवन को हैंड ओवर लेने के निर्देश दिए, वहीं कार्य में कमी होने पर संबंधित ठेकेदार या सरपंच को पूरा करने के निर्देश दिए वहीं आनाकानी करने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने और सरपंच से कुर्की करने के निर्देश दिए।

पीलिया से बचाव के लिए कलेक्टर ने बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि जहां का पाइप टूटा या छेद है उसे मरम्मत तत्काल करे। साथ ही सभी सीएमओ को शहरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

25 लाख बनाम 5 लाख: पत्रकार भवन पर संग्राम, 'प्रेस क्लब' नहीं 'पत्रकार सदन' की उठी मांग!'

सारंगढ़ /मूक पत्रिका

सारंगढ़ जिले में पत्रकारों के भवन निर्माण को लेकर घमासान तेज हो गया है। एक ओर अरुण साव द्वारा अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति को 25 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, वहीं दूसरी ओर प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा द्वारा प्रेस क्लब को 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने जिले के पत्रकारों के बीच असंतोष और आरोप-प्रत्यारोप का माहौल बना दिया है।

अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के सदस्यों ने डिप्टी सीएम का आभार जताते हुए कलेक्टर संजय कन्नौज से भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की मांग की है। उनका स्पष्ट कहना है कि 25 लाख की स्वीकृति राशि का सम्मान करते हुए उन्हें पर्याप्त जमीन दी जानी चाहिए, ताकि एक भव्य पत्रकार भवन का निर्माण हो सके। वहीं, दूसरी तरफ कलेक्टर द्वारा प्रेस क्लब को 5 डिसमिल भूमि आवंटित कर दी गई है, जिसे लेकर विवाद और गहरा गया है। जब इस विषय पर समिति के जिला अध्यक्ष नरेश चौहान ने कलेक्टर से चर्चा की, तो उनका कहना था कि ÷कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में सिर्फ 5 डिसमिल जमीन देना ही संभव है, जो आवंटित की जा चुकी है।÷

इधर, श्रमजीवी पत्रकार संघ ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। संघ के प्रवक्ता मुकेश साहू ने कहा कि भवन किसी एक संगठन के नाम पर नहीं, बल्कि ÷पत्रकार सदन÷ के नाम से बनाया जाना चाहिए, ताकि जिले के सभी पत्रकारों को समान रूप से लाभ मिल सके।

उन्होंने यह भी कहा कि चाहे 5 लाख की राशि हो या 25 लाख की स्वीकृति, दोनों ही जनप्रतिनिधियों का सम्मान है, लेकिन भवन का स्वरूप सर्वसमावेशी होना चाहिए। यह किसी एक संगठन का नहीं, बल्कि पूरे पत्रकार समाज का केंद्र बने। जिला अध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि उनकी समिति लगातार पत्रकार हित में कार्य कर रही है, हर वर्ष बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर उत्कृष्ट पत्रकारों का सम्मान भी किया जाता है। ऐसे में 25 लाख की राशि केवल एक संगठन के लिए नहीं, बल्कि पूरे जिले के पत्रकारों के लिए है।

मामला पहुंचा न्यायालय तक

पत्रकार भवन को लेकर विवाद अब न्यायालय की दहलीज तक पहुंच चुका है। एक ओर 25 लाख की बड़ी स्वीकृति, दूसरी ओर 5 डिसमिल जमीन का सीमित आवंटन–इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनेगा, यह अब प्रशासन और न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा।

अब नजरें कलेक्टर के फैसले पर

पूरे मामले में अब सभी की निगाहें कलेक्टर संजय कन्नौज के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। क्या 25 लाख की राशि के अनुरूप जमीन आवंटित होगी? क्या ÷प्रेस क्लब÷ की जगह ÷पत्रकार सदन÷ बनेगा?इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तय करेंगे कि सारंगढ़ में पत्रकारों का भविष्य किस दिशा में जाएगा। इस मौके पर नरेश चौहान जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति, देवराज दीपक कार्यकारी जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति, गोल्डी नायक जिलाध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार संघ, दीपक थवाईत जिलाध्यक्ष प्रेस क्लब व सभी संगठनों के सभी सदस्य मौजूद रहे ।

खाद्य एवं औषधि अधिकारियो ने की सारंगढ़ के होटल, गुमटी ठेलों की जांच

पीलिया और खाद्य पदार्थो के अशुद्धि की रोकथाम के लिए अभियान

सारंगढ़ बिलाईगढ़ /मूक पत्रिका

सारंगढ़ शहर के विभिन्न वार्डो मे पीलिया के केस मिलने को ध्यान में रखते हुए और खाद्य पदार्थो की अशुद्धि की रोकथाम के लिए कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे के निर्देशन में तथा अभिहित अधिकारी भारत पटेल के मार्गदर्शन में मंगलवार को शहर के विभिन्न गुमटी, ठेलो एवं होटलों का निरीक्षण किया गया जिसमें खाद्य व्यापारियों को खाद्य सामग्री ढंक कर रखने, बासी खाद्य सामग्री न रखने तथा प्रतिष्ठानों में सफाई आदि रखने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही शहर में नगरपालिका द्वारा सप्लाई किये जाने वाले पेय पानी का केमिकल एवं माइक्रोबियल जांच हेतु सर्विलांस नमूना तथा इसके अलावा मार्केट के गन्ना जूस, आम जूस, गुपचुप ठेले आदि का निरीक्षण किया गया तथा गन्ना रस, पानी व बर्फसिल्ली निर्माण करने वाले प्रतिष्ठान से बर्फपानी का विधिक नमूना तथा नोटिस दिया गया इसके साथ मार्केट में गन्ना एवं आम जूस को विक्रय किए जाने वाले बर्फ सिल्लियों को साफ़ सुथरे पानी से बनाएं जाने तथा अखाद्य बर्फ जैसे मछलियों आदि को प्रिजर्व किए जाने वाले बर्फ सिल्ली को इंडिगो कार्मिन ब्रिलियंट ब्लू रंग के बर्फ सिल्ली का उपयोग करने हेतु निर्देशित किया गया। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शांतनु भट्टाचार्य तथा वरुण पटेल उपस्थित थे।

मान्यता रायगढ़ की, संचालन पुसौर में, विकासखंड शिक्षा अधिकारी को नहीं जानकारी..? विभाग में खेल चल रहा भारी..?

शिक्षा विभाग की मिलीभगत से चल रहा आशु ज्ञान ज्योति स्कूल?

रायगढ़/मूक पत्रिका

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की जानकारी में ही नहीं और 3 वर्षों से निजी स्कूल नियम कायदों को ताक में रखकर पुसौर ब्लॉक के गांव गोर्रा में संचालित हो रहा है।

जानकारी के अनुसार आशु ज्ञान ज्योति स्कूल को मान्यता विकासखण्ड रायगढ़ के अंतर्गत दी गई है, लेकिन पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से यह स्कूल विकासखण्ड पुसौर के ग्राम गोर्रा में संचालित किया जा रहा है। नियमों के अनुसार जिस स्थान और क्षेत्र के लिए स्कूल को मान्यता दी जाती है, उसी स्थान पर विद्यालय का संचालन होना अनिवार्य होता है।

यदि स्कूल किसी अन्य स्थान पर संचालित होता है तो उसकी मान्यता निरस्त किए जाने का प्रावधान है।बावजूद इसके शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं।जो विभागीय कार्यप्रणाली की लचर व्यवस्था को सामने ला रहा है।

बच्चों के भविष्य से खिलवाड़

गौरतलब हो कि कुछ वर्षों पूर्व आशु ज्ञान ज्योति स्कूल इंग्लिश मीडियम के संचालक द्वारा स्कूल किराए के भवन में प्रारंभ की गई थी।सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार किराया जमा न करने की स्थिति में मकान मालिक द्वारा भवन खाली कार्य जाने की बात बताई गई।जिसके बाद शिक्षा विभाग को गुमराह कर ग्राम गोर्रा में जमीन खरीदी

का दावा कर स्कूल निर्माण की मोहलत मांगी गई।इस सब में मजेदार बात यह है कि उक्त स्कूल को मान्यता रायगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत प्रदान की गई थी।वही बीते तीन वर्षों से इस स्कूल में सैकड़ों बच्चों ने पढ़ाई किया।परन्तु अगर इस स्कूल की मान्यता संबंधित जांच में अन्यत्र विकासखंड से संचालन की जानकारी सामने आने पर विषम परिस्थिति खड़े होने के साथ अध्यनरत बच्चों पर भी इसका गलत असर पड़ेगा। इस मामले में शिक्षा विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है।

बताया जा रहा है कि शिक्षा अधिकारी और सीएससी के कुछ कर्मचारियों की कथित मिलीभगत के कारण यह स्कूल नियमों को दरकिनार कर संचालित किया जा रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि यदि स्कूल को रायगढ़ विकासखण्ड के कुमारपाली के लिए मान्यता मिली है तो उसे वहीं संचालित किया जाना चाहिए। नियमों के विपरीत दूसरे विकासखण्ड में स्कूल चलाना पूरी तरह से गलत है और इससे छात्रों के भविष्य पर भी असर पड़ सकता है।

बी ओ ने जताई अनभिज्ञता

बड़े आश्चर्य की बात है कि बीते तीन वर्षों से एक विकासखंड में संचालित निजी स्कूल की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारी को ही नहीं है।ऐसा हम नहीं कहते यह जानकारी स्वयं विकासखंड शिक्षाधिकारी द्वारा दी गई है।तो आखिरकार स्कूल प्रबंधन किसकी शय् पर नियम कायदों की अवहेलना करते हुए दूसरी जगह की मान्यता ले स्कूल का संचालन दूसरे जगह कर रहा है।क्या इतने वर्षों में कभी निजी स्कूलों के मान्यता की जांच करने जहमत शिक्षा विभाग द्वारा नहीं उठाई गई।या फिर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से इस स्कूल को ही जांच की दायरे से दूर रखा गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए जब इस संबंध में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि उन्हें ग्राम गोर्रा में इस स्कूल के संचालन की कोई जानकारी नहीं है।

इतना ही नहीं, उनके कार्यालय में इस संबंध में किसी प्रकार का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। इससे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं क्या कहते है विकासखंड शिक्षाधिकारी शैलेश कुमार देवांगनपुसौर =पुसौर विकासखंड में आशु ज्ञान ज्योति स्कूल का संचालन नहीं हो रहा है।यहां से उसे मान्यता नहीं कि गई है।

संक्षिप्त समाचार

खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति का बड़ा बयान

तेहरान, एजेंसी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थायी

शांति के लिए अमेरिका को पश्चिम एशिया से बाहर जाना चाहिए। इस बीच क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। ड्रोन हमले, जहाजों पर हमले और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाए जाने से वैश्विक तेल सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा और शांति के लिए अमेरिका को पश्चिम एशिया से बाहर जाना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी बात रखते हुए लिखा कि अगर इस इलाके को सुरक्षित बनाना है, तो अमेरिका की मौजूदगी यहां नहीं होनी चाहिए।

पाकिस्तान से ईरान तक चीन का 'सुपर मिसाइल शील्ड' फेल!

वाशिंगटन, एजेंसी। एक नई रिपोर्ट के अनुसार चीन का अत्याधुनिक माना जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम ।क्त-9क्रसतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में गंभीर रूप से असफल साबित हुआ है। अमेरिकी अख़बार की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की मिसाइल और रडार तकनीक, जो सैन्य परेड में प्रभावशाली दिखाई देती है, युद्ध के मैदान में फ्रअंधी, बहरी और गूंगीफ्र साबित हुई। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में तीन अलग-अलग देशों में चीन के हथियारों की क्षमता पर सवाल उठे हैं।

भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीनी HQ--B सिस्टम तैनात किया था। लेकिन भारतीय हमलों के सामने यह प्रणाली प्रभावी तरीके से न तो मिसाइलों को रोक सकी और न ही लक्ष्यों को सही तरह ट्रैक कर पाई। वेनेजुएला में चीन के JY-w|A radar सिस्टम भी विफल बताए गए। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान ये रडार कई विमानों का पता तक नहीं लगा पाए।

नेपाल में भीषण सड़क हादसा, मंदिर से लौट रहे सात भारतीय श्रद्धालुओं की मौत

नेपाल, एजेंसी। नेपाल के गोरखा जिले में शनिवार शाम एक सड़क हादसे में कम से कम सात भारतीय श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालु मनकामना मंदिर में दर्शन कर लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार श्रद्धालुओं को ले जा रही एक इलेक्ट्रिक माइक्रोबस साहिद लखन ग्रामीण नगरपालिका के कंतार क्षेत्र में सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। गोरखा जिला पुलिस कार्यालय के उप पुलिस अधीक्षक राज कुमार श्रेष्ठ ने बताया कि हादसे में सात अन्य श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए चितवन मेडिकल कॉलेज, भरतपुर (चितवन जिला) भेजा गया है। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान अभी जारी है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार माइक्रोबस में एक दर्जन से अधिक यात्री सवार थे। गोरखा के मुख्य जिला अधिकारी तुलसी बहादुर श्रेष्ठ ने बताया कि माइक्रोबस मनकामना मंदिर से पश्चिम की ओर तनहूं जिले के अनबुखैरेनी क्षेत्र की ओर जा रही थी। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मंदिर दर्शन के बाद यात्री किस स्थान की ओर जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन श्रद्धालुओं को ले जा रही इलेक्ट्रिक माइक्रोबस पहाड़ी सड़क के एक मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे पहले अगस्त 2024 में भी अनबुखैरेनी क्षेत्र में भारतीय श्रद्धालुओं से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी नेपाल में हाल के वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में वृद्धि देखी गई है। नेपाल ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक एक दशक पहले देश में 4,999 सड़क हादसे दर्ज किए गए थे, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 7,669 हो गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सड़क हादसों का सबसे ज्यादा असर कमजोर वर्गों पर पड़ता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य सिर्फ हमारे दुश्मनों के जहाजों के लिए बंद

तेहरान, एजेंसी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य खुला है और यह रणनीतिक मार्ग सिर्फ अमेरिका और इस्राइल के जहाजों के लिए बंद है। ईरानी विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की प्रमुख शक्तियों से होर्मुज जलडमरूमध्य में अपने नौसैनिक जहाज तैनात करने की अपील की है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी हाल में इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को खुला रखेगा। अराघची ने एक बातचीत के दौरान कहा, 'होर्मुज जलडमरू खुला है। यह केवल हमारे दुश्मनों, अमेरिका और उसके सहयोगियों के टैंकरों और जहाजों के लिए बंद है। बाकी सभी के लिए आवागमन पर कोई रोक नहीं है।' होर्मुज में ईरानी नाकेबंदी को लेकर किए गए सवाल पर अराघची ने कहा कि सुरक्षा

चिंताओं के चलते ये नाकेबंदी की गई है। रूस और चीन को लेकर अराघची ने कहा, 'रूस और चीन हमारे रणनीतिक साझेदार हैं। अतीत में हमारा घनिष्ठ सहयोग रहा है, जो अभी भी जारी है। इसमें सैन्य सहयोग भी शामिल है।''होर्मुज स्ट्रेट खुला है, पर नियंत्रण हमारे पास है' आईआरजीएस कमांडर

ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने बताया है कि दुनिया में तेल ले जाने का एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता होर्मुज स्ट्रेट अभी भी खुला है और उस पर ईरान का नियंत्रण बना हुआ है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की नौसेना के कमांडर अलीरेजा तंगसीरी ने एक बयान में कहा कि अमेरिका द्वारा किए जा रहे दावे सही नहीं हैं। अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान की नौसेना को नष्ट कर दिया है और तेल के जहाजों को सुरक्षित रास्ता दे सकता है, लेकिन ये बातें गलत हैं। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के हवाले से यह जानकारी दी है। बयान में कहा गया कि होर्मुज स्ट्रेट को सैन्य रूप से बंद नहीं किया गया है, बल्कि यह सिर्फ ईरान के नियंत्रण में है। होर्मुज स्ट्रेट एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक समुद्री मार्ग है। दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अपने पहले संदेश में कहा है कि ईरान इस स्ट्रेट पर अपना प्रभाव बनाए रखेगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को उन देशों से अपील की है जो इस रास्ते से तेल मंगाते हैं। उन्होंने कहा कि इन देशों को इस समुद्री मार्ग को खुला रखने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए और अमेरिका उनकी मदद करेगा। अमेरिका इस समय तेल की बढ़ती कीमतों को कम करने की कोशिश कर रहा है।

हाल ही में अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर ईरान पर हमले किए थे, जिसके बाद ईरान ने भी पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है।

शांति वार्ता के लिए रख दी ये शर्त

इस्राइल के साथ जंग रोकने को तैयार हुआ लेबनान

लेबनान, एजेंसी। लेबनान ने संकेत दिया है कि वह इस्राइल के साथ सीधे शांति वार्ता के

लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए पहले युद्धविराम लागू होना जरूरी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, यह पहल ऐसे समय सामने आई है जब इस्राइल लेबनान में 2006 के युद्ध के बाद सबसे बड़े जमीनी अभियान की चेतावनी दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने करीबी सलाहकार रॉन डर्मर को लेबनान से जुड़े कूटनीतिक प्रयासों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी है। वहीं अमेरिकी पक्ष से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के वार्ता में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बातचीत आने वाले दिनों में शुरू हो सकती है और इसके लिए पेरिस या साइप्रस संभावित स्थान हो सकते हैं। इस बीच फ्रांस की ओर से एक शांति प्रस्ताव की चर्चा भी सामने आई है, जिसमें युद्ध खत्म करने के लिए हिजबुल्ला के निरस्त्रीकरण और लेबनान द्वारा इस्राइल को मान्यता देने की शर्तों का उल्लेख किया गया था। हालांकि फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने ऐसे किसी प्रस्ताव से इनकार किया है। लेबनान के संसदीय अध्यक्ष और अमल मूवमेंट के नेता नबीह बेरी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी वार्ता से पहले युद्धविराम लागू होना आवश्यक है। उधर पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अमेरिकी बल ईरानी सैन्य क्षमताओं के खिलाफ अभियान जारी रखे हुए हैं।

दक्षिणी लेबनान में इस्राइल के हमले जारी

इसी दौरान प्रेस टीवी की रिपोर्ट में दावा किया गया कि एक इराकी प्रतिरोधी समूह ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इराक में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले के बाद आग लग गई। ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने भी दावा किया है कि उन्होंने चार और ड्रोन मार गिराए हैं, जिसके बाद अब तक गिराए गए ड्रोन की संख्या 118 हो गई है। दक्षिणी लेबनान में भी झड़पें जारी हैं। अल जजीरा के अनुसार, इस्राइली हवाई हमलों और तोपखाने की गोलाबारी ने कई कस्बों को निशाना बनाया। मेफदून और उसके आसपास के इलाकों के अलावा जवतर, यहमर और अर्नौन जैसे शहरों में भी भारी गोलाबारी की खबर है।

तेल में लगेगी आग?: खार्ग पर हमले के बाद पलटवार के मूड में ईरान, यूएई के तीन बंदरगाहों पर हमले की कर रहा तैयारी

यूएई, एजेंसी। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के कुछ बड़े बंदरगाहों के पास धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई। इसी बीच ईरान ने यूएई के लोगों को दुबई, अबू धाबी और फुजैराह के बड़े बंदरगाहों के आसपास के इलाकों को तुरंत खाली करने की चेतावनी दी है। दरअसल, यह चेतावनी उस समय आई जब अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप स्थित तेल केंद्र पर हमला किया। खार्ग द्वीप ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और यहां से देश के लगभग 90 प्रतिशत कच्चे तेल का निर्यात होता है। ईरान की समाचार एजेंसी तसनीम ने लोगों से दुबई के जेबेल अली पोर्ट, अबू धाबी के खलीफा पोर्ट और फुजैराह पोर्ट के आसपास से दूर रहने को कहा। एजेंसी के अनुसार इन इलाकों में अमेरिकी सैन्य बल मौजूद हैं और

इसलिए ये स्थान वैध सैन्य लक्ष्य बन सकते हैं। ईरान की इस चेतावनी के बाद उसकी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने भी यूएई के नेतृत्व को कड़ा संदेश दिया। संगठन के प्रवक्ता इब्राहिम जोलफाघरी ने कहा कि अगर यूएई के शहरों के अंदर अमेरिकी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहां के बंदरगाह और सैन्य सुविधाएं ईरान के निशाने पर हो सकती हैं। इस बीच यूएई प्रशासन ने बताया कि एक ड्रोन को मार गिराया गया था और उसके मलबे के कारण आग लग गई। फुजैराह क्षेत्र में दिखाई दिया धुआं इसी घटना से जुड़ा माना जा रहा है। फुजैराह का इलाका तेल भंडारण और व्यापार का बड़ा केंद्र है और यहां महत्वपूर्ण निर्यात टर्मिनल भी स्थित है। इस बीच यूएई के विदेश मंत्रालय ने भी क्षेत्र में हो रहे हमलों की निंदा की है और कहा है कि जब तक हमले जारी रहेंगे, तब तक किसी भी तरह की मध्यस्थता या शांति वार्ता संभव नहीं है। कुल मिलाकर, अमेरिका-ईरान टकराव के कारण पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है और यह संकट अब वैश्विक ऊर्जा बाजार और समुद्री व्यापार के लिए भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है।उधर अमेरिका ने भी पुष्टि की है कि उसके सैन्य अभियान में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार 90 से अधिक सैन्य लक्ष्यों पर हमले किए गए, जिनमें मिसाइल और नौसैनिक हथियारों के भंडार शामिल थे। रिपोर्टों के अनुसार कुवैत से लेकर ओमान तक कई तेल और गैस सुविधाओं पर हमले हुए हैं। इनमें सऊदी अरब की रास तनुरा रिफाइनरी, कतर का रास लाफान गैस प्लांट और यूएई की रुवैस रिफाइनरी जैसी बड़ी ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं।

भारत आ रहे एलपीजी गैस टैंकरों को मिलेगी सुरक्षा, फारस की खाड़ी के पास नौसेना के युद्धपोत तैनात

ईरान, एजेंसी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी के पास अपने कई युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार ये युद्धपोत भारत आने वाले व्यापारिक जहाजों को जरूरत पड़ने पर सहायता देने के लिए तैयार रखे गए हैं। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि भारतीय नौसेना के जहाजों को इस क्षेत्र में इसलिए तैनात किया गया है, ताकि भारतीय व्यापारिक जहाजों और उनके चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी बीच शनिवार को ईरानी अधिकारियों ने भारत की ओर जा रहे दो भारतीय झंडे वाले एलपीजी जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी। इनमें से एक जहाज शिवालिक है, जो जहाज निगरानी वेबसाइट के अनुसार फिलहाल ओमान के पास देखा गया था। इसके 21 मार्च तक अपने गंतव्य पर पहुंचने की संभावना है। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को फारस की खाड़ी क्षेत्र की समुद्री स्थिति, भारतीय नाविकों और जहाजों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार फारस की खाड़ी में 24 भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर 668 भारतीय नाविक काम कर रहे हैं, जबकि होर्मुज जलडमरूमध्य के पूर्व में तीन जहाजों पर 76 भारतीय नाविक मौजूद हैं। मंत्रालय ने बताया कि डीजी शिपिंग जहाज मालिकों, आरपीएसएल एजेंसियों

और भारतीय मिशनों के साथ समन्वय बनाए हुए है। सभी जहाजों और चालक दल की लगातार निगरानी की जा रही है। 24 घंटे के नियंत्रण कक्ष के सक्रिय होने के बाद से अब तक 2,425 से अधिक कॉल और 4,441 ईमेल प्राप्त हुए हैं। 223 से ज्यादा फंसे भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई है।

भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने भी कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद ईरान भारत की ओर जाने वाले जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित रास्ता देगा। उन्होंने भारत और ईरान को पुराने मित्र बताते हुए कहा कि दोनों देशों के हित और भविष्य जुड़े हुए हैं।

वहीं भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि ईरान कभी भी होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करना नहीं चाहता था। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा हालात के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है और दुनिया के नेताओं को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर युद्ध रोकने का दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि बढ़ती तेल कीमतों से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है।

● जारी संघर्ष का असर वैश्विक समुद्री सुरक्षा पर साफ नजर आने लगा

पश्चिम एशिया के समुद्री मार्गों पर हमले, अब तक 17 जहाजों को बनाया गया निशाना

ओमान, एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर वैश्विक समुद्री सुरक्षा पर साफ नजर आने लगा है। पिछले दो हफ्तों में क्षेत्र के प्रमुख समुद्री मार्गों पर कम से कम 17 जहाजों पर हमले हुए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार को लेकर चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार ये घटनाएं फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी के आसपास हुई हैं। ऐसे में लगातार हो रहे हमलों और ड्रोन गतिविधियों ने इस पूरे समुद्री क्षेत्र को बेहद संवेदनशील बना दिया है। इस बात की जानकारी सीएनएन ने यूनाइटेड किंगडम मरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) के डेटा का हवाला देते हुए दी है। ये हमले एक मार्च से फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी के आसपास हुए हैं। इतना ही नहीं इन हमलों में एक भारतीय नागरिक की मौत भी हो चुकी है। संघर्ष के बीच समुद्री मार्गों पर हो रहे हमलों के बीच जॉइंट मरीटाइम इन्फॉर्मेशन सेंटर (जेएमआईसी) और यूकेएमटीओ ने चेतावनी जारी की है कि फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान

की खाड़ी में समुद्री खतरा गंभीर है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य में सामान्य रूप से रोजाना लगभग 138 जहाज गुजरते हैं, लेकिन अब सिर्फ 2 जहाज प्रतिदिन गुजर रहे हैं। हमले अब सिर्फ पश्चिमी देशों के जहाजों पर नहीं हो रहे, बल्कि सभी देशों और प्रकार के जहाज प्रभावित हैं। हाल ही में फुजैरा ऑयल टर्मिनल पर हमला हुआ, जिससे पता चलता है कि अब पोर्ट और ईंधन आपूर्ति सुविधाएं भी निशाना बन रही हैं।

जारी हमलों के बीच समुद्री क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक व्यवधान भी तेजी से बढ़ रहे हैं। जहाजों के नेविगेशन सिस्टम में जीएनएसएस और जीपीएस से जुड़ी गड़बड़ी, जामिंग और स्पूफिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे जहाजों की सही लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो रहा है। एआईएस डेटा के अनुसार कई जहाज ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो 30 नॉट्स से ज्यादा की असंभव गति से चलते हुए दर्ज हो रहे हैं या उनकी लोकेशन जमीन पर दिख रही है। यह तकनीकी बाधाएं सिर्फ फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका असर रेड सी और बाब-एल-मांडब जलडमरूमध्य तक भी देखा जा रहा है। ऐसे में इस स्थिति का असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ रहा है।

समुद्री क्षेत्र में बढ़ते खतरे के कारण युद्ध-जोखिम बीमा की कीमतें बढ़ गई हैं।

ईरान युद्ध के बीच फर्जी एआई वीडियो से प्रोपेगैंडा फैलाने का आरोप, यूएई में 10 गिरफ्तार

अबुधावी, एजेंसी। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूएई में ईरान युद्ध को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही इन लोगों के खिलाफ त्वरित सुनवाई के आदेश दिए हैं। सरकारी समाचार एजेंसी वाम के अनुसार यूएई के अटॉर्नी जनरल डॉ. हमद सैफ अल शम्सी ने कहा कि सोशल मीडिया की निगरानी के दौरान ऐसे वीडियो सामने आए, जिनमें लोगों को गुमराह करने वाली सामग्री साझा की गई। आरोपियों की राष्ट्रीयता का खुलासा नहीं किया गया है। जांच में पाया गया कि कुछ वीडियो में वास्तविक फुटेज का इस्तेमाल करते हुए उन्हें गलत संदर्भ में पेश किया गया। वहीं, कई क्लिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किए गए थे। इनमें विस्फोट, प्रमुख इमारतों पर हमले या यूएई के अलग-अलग इलाकों में बड़े पैमाने पर आग लगने जैसे दृश्य दिखाए गए थे। अटॉर्नी जनरल के अनुसार, कुछ वीडियो में बच्चों की भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा खतरे का झूठा संकेत दिया गया। वहीं, अन्य क्लिप में विदेशी घटनाओं को यूएई से जोड़कर दिखाया गया। उनका कहना है कि ऐसे प्रयासों का उद्देश्य लोगों को भ्रमित करना और डर का माहौल पैदा करना था। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और उन्हें हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस तरह के अपराधों के लिए कम से कम एक वर्ष की जेल और 1 लाख दिरहम से कम नहीं जुर्माने का प्रावधान है। अटॉर्नी जनरल ने साफ चेतावनी दी है कि साइबर स्पेस या नई तकनीक का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं होगा। देश की सुरक्षा और शांति से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे रक्षा प्रणालियों से जुड़े वीडियो या ऐसी कोई भी जानकारी शेयर न करें जिससे समाज में डर पैदा हो।

ईरान में सत्ता परिवर्तन की उम्मीदें धूमिल, इस्राइली पीएम नेतन्याहू के सामने नई चुनौती

इस्लायल, एजेंसी। ईरान के खिलाफ युद्ध में सैन्य हमलों और शीर्ष नेतृत्व पर हमले के बावजूद तेहरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना कमजोर पड़ती दिख रही है। ऐसे में इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब एक नई राजनीतिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। इस्राइली सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व अब इस युद्ध को मध्य पूर्व की रणनीतिक तस्वीर बदलने वाली कार्रवाई के रूप में पेश कर रहा है, जबकि तेहरान में शासन परिवर्तन का लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राइल के सैन्य व राजनीतिक नेतृत्व की ओर से ईरान के खिलाफ युद्ध को मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन को बदल देने वाली कार्रवाई बताया जा रहा है। तेल अवीव स्थित पत्रकार और यूएस-इस्राइल थिंक टैंक इस्राइल पॉलिसी फोरम से जुड़े नीति सलाहकार नेरी जिलबर के अनुसार, नेतन्याहू इस युद्ध को ऐतिहासिक जीत बताने की कोशिश कर रहे हैं। यदि तेहरान की मौजूदा सत्ता कमजोर या समाप्त हो जाती, तो लेबनान में हिज्बुल्लाह और गाजा में हमास जैसे समूहों को मिलने वाली वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और हथियारों की आपूर्ति पर गहरा असर पड़ सकता था। इस्राइल का मानना रहा है कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण पूरी तरह बदल सकता है। इस्राइल ने कई बार ईरानी जनता से मौजूदा

व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील भी की। इस्राइल के भीतर कुछ लोग नेतन्याहू के इन संकेतों को इस रूप में देख रहे हैं कि संभवतः युद्ध को समाप्त करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ती तेल कीमतों के कारण अमेरिका की सरकार पर भी संघर्ष समाप्त करने का दबाव बताया जा रहा है। जून 2025 के बाद सिर्फ आठ महीने में ही इस्राइल फिर युद्ध में लौट आया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान मिसाइल कार्यक्रम फिर खड़ा कर रहा था और उसे तथा अपने परमाणु कार्यक्रम को गहराई में भूमिगत ले जाने की योजना बना रहा था।

ईरानी सुरक्षा व्यवस्था में तनाव के संकेत

इस्राइल के अखबार येदियोथ अहरोनोथ के रक्षा संवाददाता ने लिखा है कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के भीतर आंतरिक तनाव व कुछ मामलों में सैनिकों के पलायन जैसी घटनाएं सामने आई हैं। नेतन्याहू का संकेत है कि इस्राइल युद्ध के जरिए परिस्थितियां बदल पीछे हट सकता है। हालांकि तेहरान में सत्ता बरकरार रहने की स्थिति नेतन्याहू के लिए जोखिम भी पैदा कर सकती है। विश्लेषक नेरी जिलबर के अनुसार, नेतन्याहू की पूर्ण विजय की घोषणाएं वास्तविकता में नहीं बदलतीं हैं तो यह उनके खिलाफ जा सकता है।

चिन्नास्वामी को आईपीएल मैच होस्ट करने की परमीशन मिली

● आरसीबी की विक्ट्री सेरेमनी में भगदड़ के बाद रोक लगी थी; यहां ओपनिंग मैच

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक सरकार ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल 2026 के मैचों के आयोजन को मंजूरी दे दी है। यहां 28 मार्च को मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ओपनिंग मैच खेला जाएगा।

कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) प्रवक्ता विनय मृत्युंजय ने बताया कि एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों और तैयारियों की समीक्षा के बाद यह परमीशन मिली है।

कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने सोमवार को एक्सपर्ट कमेटी,केएससीए, आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए के साथ बैठक की। इसमें एक्सपर्ट कमेटी ने स्टेडियम की सुरक्षा और तैयारियों पर अपनी रिपोर्ट पेश की।

एक साल पहले आरसीबी की पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत के बाद स्टेडियम में

विक्ट्री परेड हुई थी। लेकिन स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

विमेंस वर्ल्ड कप के मैच शिफ्ट हुए थे

विमेंस वर्ल्ड कप के समय जस्टिस डी'कुन्हा कमेटी ने भी इस ग्राउंड को बड़े आयोजनों के लिए असुरक्षित बताया था। इस रिपोर्ट के बाद आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के मैच भी बेंगलुरु से हटाकर नवी मुंबई में कराए गए। वहीं घरेलू टी-20 लीग महाराजा टी-20 ट्रॉफी को भी बेंगलुरु की जगह मैसूर में शिफ्ट करना पड़ा था।

आईपीएल के शुरुआती 20 मैच का शेड्यूल जारी

4 दिन पहले बीसीसीआई ने आईपीएल के शुरुआती 20 मैचों का शेड्यूल जारी किया था। इनमें से 2 मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने हैं। शेड्यूल जारी करते समय बीसीसीआई ने कहा था कि बेंगलुरु में आईपीएल मैच सरकार की परमीशन पर निर्भर करेंगे।

बीसीसीआई के नमन अवॉर्ड 2026 सम्मान

शुभमन गिल और स्मृति मंधाना इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय कप्तान शुभमन गिल और स्मृति मंधाना को रविवार को बीसीसीआई इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ ईयर चुना गया है। साथ ही बीसीसीआई ने 1983 वर्ल्डकप विजेता टीम के सदस्य रोजर बिन्नी और पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। दरअसल बीसीसीआई ने रविवार को दिल्ली में नमन अवॉर्ड 2026 का आयोजन कर रहा है। इस दौरान भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को बीसीसीआई लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया गया।साथ ही अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे को डोमेस्टिक में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए लाला अमरनाथ अवॉर्ड के लिए चुना गया। इसके अलावा 2024-26 तक पांच आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाली पांचों टीमों को सम्मानित किया गया। इसमें मेंस टी-20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वूमंस वर्ल्ड कप के अलावा, अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली मेंस-वूमंस टीमें शामिल रहीं।

द्रविड़ को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार (2024-25)

- महिला वनडे में सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा
- महिला वनडे में सबसे ज्यादा रन स्मृति मंधाना
- महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू श्री चारणी
- पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू हर्षित राणा
- महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर मंधाना

पॉली उमरीगर अवॉर्ड (पुरुष)

- सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर शुभमन गिल
- सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड
- रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़, मिताली राज

लाला अमरनाथ अवॉर्ड

- घरेलू लिमिटेड-ओवर्स प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ ऑल-राउंडर आयुष म्हात्रे (मुंबई)
- रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑल-राउंडर हर्ष दुबे

जगमोहन डालमिया ट्रॉफी

- सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर (जूनियर घरेलू) इरा जाधव (मुंबई)
- सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर (सीनियर घरेलू-सीनियर महिला वनडे) शेफाली वर्मा (हरियाणा)
- विजय मर्चेंट ट्रॉफी (अंडर-16) एलीट ग्रुप में सबसे ज्यादा विकेट यशबर्धन सिंह चौहान (मध्य प्रदेश)
- प्लेट ग्रुप में सबसे ज्यादा विकेट

किशन सरकार (त्रिपुरा)

- एलीट ग्रुप में सबसे ज्यादा रन शांतनु सिंह (उत्तर प्रदेश)
- प्लेट ग्रुप में सबसे ज्यादा रन प्रीतम राज (बिहार)
- माधवराव सिंधिया अवॉर्ड-रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप में सबसे ज्यादा विकेट हर्ष दुबे
- प्लेट ग्रुप में सबसे ज्यादा विकेट सुचित जे
- एलीट ग्रुप में सबसे ज्यादा रन वाईवी राठौड़
- प्लेट ग्रुप में सबसे ज्यादा रन स्नेहल कौथनकर

अन्य पुरस्कार

- घरेलू टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन
- घरेलू क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ अंपायर उल्हास गांधे (विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन)

बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज की हार नहीं पचा सका पाकिस्तान, 2-1 से जीती सीरीज

अंपायर पर बड़ा आरोप लगाकर दर्ज की शिकायत

मीरपुर (एजेंसी)बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। ढाका में खेले गए तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने अंतिम ओवर तक लड़ाई लड़ी लेकिन उन्हें 11 रनों से शिकस्त मिली। इस हार के बाद अब पाकिस्तानी टीम ने आईसीसी के सामने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अंपायर के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश ने एकतरफा जीत हासिल की। इसके बाद दूसरा मैच पाकिस्तान ने अपने नाम किया। तीसरे मैच में बांग्लादेश ने जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम कर ली। ये सीरीज विवादों से भरी रही है। इससे पहले दूसरे वनडे मैच के दौरान बांग्लादेशी कप्तान मेंहदी हसन मिराज ने पाकिस्तान के सलमान अली आगा को विवादित तरीके से रन आउट किया था। अब तीसरे मैच में पाकिस्तान ने अंपायर पर बांग्लादेश टीम का साथ देने का आरोप लगाया है। क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का मानना है कि गेंद का बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले दिखा था। इसके बाद ही बांग्लादेश ने रिव्यू लेने का फैसला किया। पाकिस्तान को लगा कि बांग्लादेश ने 15 सेकंड की समय सीमा के बाद रिव्यू की मांग की थी। हालांकि, उन्हें 15 सेकंड के भीतर ही रिव्यू लेना चाहिए था।

इंडियन वेल्स 2026

सिनर और सबालेंका ने जीते खिताब

कैलिफोर्निया (एजेंसी)। अमेरिका के कैलिफोर्निया में खेले गए इंडियन वेल्स ओपन में इटली के जैनिक सिनर और बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने खिताब जीता। मेन्स सिंगल्स के फाइनल में सिनर ने रूस के डैनियल मेदवेदेव को हराकर अपना पहला इंडियन वेल्स टाइटल जीता।

वहीं, विमेंस सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर-1 आर्यना सबालेंका ने एलिना रायबाकिना के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए ट्रॉफी अपने नाम की।

सिनर फेडरर और जोकोविच के क्लब में शामिल हुए

सिनर ने इस जीत के साथ हार्ड कोर्ट पर होने वाले सभी बड़े खिताब अपने नाम कर लिए हैं। इनमें छह एटीपी मास्टर्स 1000, निट्टो एटीपी फाइनल्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन शामिल हैं।

इससे पहले यह उपलब्धि सिर्फ रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के नाम थी। सिनर ने 2023 में टोरंटो में अपना पहला मास्टर्स 1000 खिताब जीता था और अगले तीन सालों के भीतर ही उन्होंने हार्ड कोर्ट के सभी बड़े एलीट खिताब अपने नाम कर लिए।सिनर ने 2023 में टोरंटो में अपना पहला मास्टर्स 1000 खिताब जीता था।

जैनिक सिनर ने फाइनल में पहला सेट टाईब्रेक में 7-6 (8-6) से जीता। इसके बाद दूसरे सेट में भी कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन सिनर ने इसे 7-6 (7-4) से अपने नाम कर लिया।

खास बात यह रही कि सिनर ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी सेट नहीं गंवाया और सीधे सेटों में जीत दर्ज करते हुए पहली बार इंडियन वेल्स मास्टर्स वेल्स की ट्रॉफी अपने नाम की।

सबालेंका ने चैंपियनशिप पॉइंट बचाया और मैच जीता

विमेंस सिंगल्स का फाइनल में आर्यना सबालेंका ने एलिना रायबाकिना को 3-6, 6-3, 7-6 (8-6) से हराया। सबालेंका पहला सेट हार गई थीं, लेकिन उन्होंने जबरदस्त वापसी की।

तीसरे सेट के टाइ-ब्रेकर में मुकाबला इतना फंस गया था कि रायबाकिना के पास चैंपियनशिप पॉइंट था, लेकिन सबालेंका ने उसे बचाया और जीत हासिल की। यह सबालेंका का पहला इंडियन वेल्स खिताब है। इससे पहले वह दो बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में हार चुकी थीं।

रायबाकिना से पुराना हिसाब चुकता किया

साल 2023 के इंडियन वेल्स फाइनल में एलिना रायबाकिना ने ही सबालेंका को हराकर खिताब जीता था। इस बार सबालेंका ने उस हार का बदला ले लिया।

गुलवीर सिंह ने रचा इतिहास, न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन 2026 में तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के स्टार लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने रविवार को न्यूयॉर्क में पुरुषों की हाफ-मैराथन (21किमी) का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक रिलीज के अनुसार 27 वर्षीय सेना के धावक ने न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन 2026 में 59:42 का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया।

दक्षिण अफ्रीका के एड्रियन वाइल्डशट 59:30 के समय के साथ पहले स्थान पर रहे, उनके बाद मोरक्को में जन्मे अमेरिकी लंबी दूरी के धावक जुहैर तालबी रहे जिनका समय 59:41 था। पिछला नेशनल रिकॉर्ड 1:00:30 का था जिसे स्टीपलचेज विशेषज्ञ अविनाश साबले ने 2020 में दिल्ली हाफ मैराथन में बनाया था।

सिंह कई नेशनल रिकॉर्ड रखने वाले पहले भारतीय लंबी दूरी के धावक हैं जिनके रिकॉर्ड 3,000द्व ट्रैक से लेकर 25द्यद्व रोड रेस तक हैं। एशियाई खेलों के पदक विजेता के नाम पुरुषों की 5,000द्व और 10,000द्व ट्रैक रेस के रिकॉर्ड भी हैं। सिंह का 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था जिसमें उन्होंने 5,000द्व और 10,000द्व दोनों ट्रैक रेस जीती थीं।

सिंह इस साल जुलाई में होने वाले ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स और सितंबर में होने वाले एशियाई खेलों, दोनों में पोडियम पर जगह बनाने का पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह फिट हूं और आने वाली बड़ी अंतरराष्ट्रीय रेस में अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रहा हूं। सेना के यह धावक फिलहाल अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स में रह रहे हैं।

स्कोरिंग सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं, 21 अंक की प्रणाली बेहतर: साइना नेहवाल

नईदिल्ली (एजेंसी)। ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने बैडमिंटन की वैश्विक संस्था बेडमिटन वर्ल्ड फेडरेशन से स्कोरिंग सिस्टम में प्रस्तावित बदलाव को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। साइना का मानना है कि मौजूदा तीन गेम की 21 अंक वाली प्रणाली खेल की गति, प्रतिस्पर्धा और खिलाड़ियों की सहनशक्ति को बेहतर तरीके से परखती है। दरअसल बीडब्ल्यूएफ ने वर्तमान तीन गेम की 21 अंक वाली प्रणाली को बदलकर तीन गेम की 15 अंक वाली प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर 25 अप्रैल को डेनमार्क के हार्सेंस में होने वाली बीडब्ल्यूएफ की वार्षिक आम बैठक में मतदान

किया जाएगा। साइना ने कहा कि बैडमिंटन की परंपरा काफी समृद्ध है और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप तथा बीडब्ल्यूएफ जैसे टूर्नामेंट खिलाड़ियों की गति और सहनशक्ति की असली परीक्षा लेते हैं। उन्होंने कहा कि स्कोरिंग सिस्टम या प्रारूप में किसी भी बदलाव पर बहुत सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए क्योंकि खिलाड़ी मौजूदा 21 अंक की प्रणाली के साथ अच्छी तरह तालमेल बैठा चुके हैं। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर के लिए प्रस्तावित नए प्रारूप के अनुसार एशिया और यूरोप में होने वाले पांच सुपर 1000 टूर्नामेंट में एकल वर्ग में 48 खिलाड़ी पहले ग्रुप चरण में खेलेंगे, जिसके बाद नॉकआउट मुकाबले होंगे। वहीं युगल स्पर्धा में 32 जोड़ियों का नॉकआउट ड्रॉ होगा और प्रत्येक सुपर 1000 टूर्नामेंट 11 दिन तक चलेगा। साइना ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन कैलेंडर काफी व्यस्त है और खिलाड़ियों को आराम के लिए बहुत कम समय मिलता है। उनके अनुसार बैडमिंटन शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण खेल है, जिसमें लंबी रैलियां होती हैं और खिलाड़ी लगभग हर सप्ताह टूर्नामेंट खेलते हैं। ऐसे में पर्याप्त रिकवरी का समय बेहद जरूरी है। साइना ने भारतीय शटलर लक्ष्य सेन की भी तारीफ की, जो हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियस में पुरुष एकल के फाइनल में पहुंचे थे।

बैसाखियों के सहारे अवॉर्ड्स समारोह में पहुंचे क्रिकेटर हर्षित राणा

● आईपीएल 2026 से पहले केकेआर को बड़ा झटका

मुंबई (एजेंसी)। आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 सीजन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की चिंताएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट के कारण पूरी तरह फिट नहीं हैं और उनके इस सीजन में खेलने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। हाल ही में एक अवॉर्ड समारोह के दौरान उन्हें बैसाखियों के सहारे चलते देखा गया, जिससे उनकी चोट और रिकवरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगर वह समय पर फिट नहीं हो पाए, तो यह केकेआर के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।

हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित बीसीसीआई नमन अवार्ड में हर्षित राणा भी शामिल हुए। यह समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जहां उन्हें बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू (मेन्स) का सम्मान दिया गया। हालांकि समारोह के दौरान राणा को बैसाखियों के सहारे चलते हुए देखा गया। उनकी यह स्थिति देखकर फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञों के बीच उनकी फिटनेस को लेकर चिंता बढ़ गई।

मंच तक नहीं जा सके हर्षित राणा

समारोह का एक भावुक पल तब सामने आया जब हर्षित राणा स्टेज तक चलकर जाने में असमर्थ दिखे। ऐसे में अरुण धूमल जो आईपीएल के चेयरमैन हैं, खुद मंच से नीचे आए और उन्हें सम्मान प्रदान किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद क्रिकेट प्रशंसकों के बीच यह सवाल उठने लगा कि क्या हर्षित राणा समय पर पूरी तरह फिट हो पाएंगे।

कब लगी थी हर्षित राणा को चोट

हर्षित राणा को इस साल टी20 विश्व कप 2026 के दौरान चोट लगी थी। दरअसल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए एक वॉर्म-अप मैच में उनके घुटने में गंभीर चोट लग गई थी। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। उनकी जगह टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया था।

मुंबई में कराई घुटने की सर्जरी

चोट के बाद हर्षित राणा ने 9 फरवरी को मुंबई में अपने घुटने की सर्जरी कराई। डॉक्टरों के अनुसार इस तरह की चोट से पूरी तरह उबरने में आमतौर पर दो से तीन महीने का समय लग सकता है। हालांकि उनकी सर्जरी सफल रही है, लेकिन मैदान पर वापसी को लेकर अभी भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

आयुष मेडिकल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक व होली मिलन संपन्न, चिकित्सकों ने मनाया उत्सव

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

आयुष मेडिकल एसोसिएशन जांजगीर-चांपा की जिला इकाई द्वारा 15 मार्च 2026 को होटल सुमित इन में वार्षिक बैठक एवं होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलेभर के चिकित्सकों ने अपने परिवार सहित उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. नागेंद्र शर्मा (अध्यक्ष, आयुष मेडिकल एसोसिएशन कोरबा एवं संचालक पतंजलि चिकित्सालय) रहे, जबकि अध्यक्षता डॉ. आर. एस. सराफ ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. वर्षा सराफ उपस्थित रहीं। होली मिलन के अवसर पर सभी चिकित्सकों एवं उनके परिजनों ने एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दीं। बच्चों ने भी इस दौरान जमकर उत्सव का आनंद लिया। मुख्य अतिथि डॉ. शर्मा ने अपने संबोधन में चिकित्सकों को सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य करने, निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाने एवं सेवा भाव से समाज के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण तब रहा जब डॉ. नागेंद्र शर्मा को आयुर्वेद के प्रति उनके समर्पण, ÷हर घर आयुर्वेद÷ मुहिम तथा विगत 20 वर्षों से निशुल्क चिकित्सकीय परामर्श देने के लिए एसोसिएशन एवं मेकशाइन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में डॉ. अजय राठौर एवं उनकी पत्नी डॉ. स्वर्ण प्रभा राठौर ने युगल गीत प्रस्तुत कर समां बांधा, वहीं डॉ. योगेंद्र साहू के गीतों पर उपस्थित चिकित्सक व उनके परिवार झूमते नजर आए। कार्यक्रम में डॉ. लक्ष्मी प्रियम स्वर्णकार, डॉ. आर.आर. पालेकर, डॉ. रामकुमार चंद्रा (जैजैपुर), डॉ. ओमप्रकाश, डॉ. श्यामा चरण साहू (मेडिकल ऑफिसर), डॉ. विकास राठौर, डॉ. रवि श्रीवास, डॉ. आकांक्षा साहू, डॉ. मंजू राठौर सहित अनेक चिकित्सक उपस्थित रहे। साथ ही मेकशाइन फार्मा प्रा. लि. के डायरेक्टर मनोज चंद्रा, आशीष कश्यप (आरएसएम), गौरव साहू एवं अक्षय राठौर (एचआर मैनेजर) भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अंत में जिला अध्यक्ष डॉ. सुरेन्द्र मिश्रा ने अपने उद्बोधन में परिवार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक चिकित्सक तभी निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर सकता है, जब उसे परिवार का सहयोग प्राप्त हो।

कांग्रेस का विधानसभा घेराव रहा पूरी तरह विफल - केदार कश्यप

कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी के आंतरिक मुद्दों को लेकर आंदोलन करती है - केदार कश्यप

रायपुर/मूक पत्रिका

वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के 'मनरेगा बचाव संग्राम' के नाम पर किए जा रहे विधानसभा घेराव को पूरी तरह विफल बताते हुए इसे कांग्रेस का 'भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम' बताया है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी जिस तरह से 'विधानसभा घेराव' का यह नाटक कर रही है, वह उनके राजनीतिक दिवालिएपन और हताशा का सबसे बड़ा सबूत है। कांग्रेस को मनरेगा के नाम बदलने से ज्यादा 'वीबी-जी रामजी' योजना लागू होने से है। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को सिर्फ भगवान राम के नाम से तकलीफ है। वन एवं सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक परिवार के नाम से संचालित योजनाओं से खुशी मिलती है तभी तो देश भर में सभी योजनाओं के नाम एक परिवार के नाम से कांग्रेस पार्टी संचालित करती रही है। वीबी जी-राम-जी योजना से रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीणों को 100 दिन के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है इसके साथ ही एक सप्ताह के भीतर में मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना अंतर्गत सामुदायिक भवन निर्माण, तालाब निर्माण, मछली पालन, नाली निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष गड्ढा खोदने का काम ही किया जाता रहा जो बारिश आते ही पट जाता था। इसके साथ ही इस योजना के तहत भारी भ्रष्टाचार भी होता था। वन एवं सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि कांग्रेस द्वारा एलपीजी सिलेंडर को लेकर केवल भ्रम फैलाया जा रहा है एवं जनता के बीच दहशत का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि देश में देश में एलपीजी का स्टॉक भरपूर है और वितरण में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश एक सशक्त राष्ट्र बन रहा है और आज के हालात बताते है कि जब पूरी दुनिया युध्द के चलते आर्थिक संकटों से जूझ रही है वहीं भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी दृष्टि के चलते अपनी विकास की रफ्तार को कोई कमी नहीं आने दिया। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके शासनकाल में रसोई गैस के लिए लंबी कतारें लगती थीं और ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 10 प्रतिशत परिवारों के पास ही गैस कनेक्शन था, जबकि आज यह संख्या 90 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। भाजपा सरकार ने उज्ज्वला योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से घर-घर गैस पहुंचाकर माताओं और बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाई है। उन्होंने कहा कि भारत के पास गैस और तेल के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं और प्रदेश में भी गैस, तेल तथा खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस के नेता जानबूझकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे आमजन में घबराहट फैले और लोग अनावश्यक रूप से वस्तुओं का भंडारण करने लगें।

प्रधान जिला न्यायाधीश व कलेक्टर ने किया जिला जेल का निरीक्षण

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये निर्देशानुसार बोर्ड आफ विजिटर्स के द्वारा जिला जेल जांजगीर का निरीक्षण प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा शक्ति सिंह राजपूत, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर मनोज कुमार कुशवाहा, कलेक्टर जन्मेजय महोबे, नगर पुलिस अधीक्षक जांजगीर सुश्री योगिता खापेडे एवं सिटी कोतवाली निरीक्षक जे पी गुप्ता की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक डी.डी. टोडर, अधिवक्ता लीगल एट डिफेंस काउंसिल सत्यनारायण सिंह ठाकुर, विनोद कुमार कश्यप, विष्णु प्रसाद अग्रवाल, अशोक यादव, पैरा लीगल वालेंटियर लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल, जयराम गढ़ेवाल सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान बंदियों को दी जाने वाली विधिक सहायता के संबंध में जिला जेल लीगल एड क्लिनिक की व्यवस्थाओं, जेल में स्थापित व्हीसी कक्ष, जेल बिल्डिंग की व्यवस्था, बैरकों के निर्माण, मुलाकात कक्ष, बंदियों को प्रदत सुविधा, भोजन की गुणवत्ता, शिकायत पेटी, पेयजल की व्यवस्था, बंदियों की कपड़ा की दशा, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था के साथ-साथ बंदियों के प्रकरण में आने वाली समस्याओं के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

नशापन समाज के लिए अभिशाप, इस पर पूर्णतः नकेल कसने कठोर कार्रवाई करें: कलेक्टर

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिलाधिकारियों की नार्कोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की बैठक लेकरच विस्तृत समीक्षा की।?कलेक्टर ने नशे के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाने के सख्त निर्देश दी है। उन्होंने जिले में नशे के कारोबार पर नकेल कसने और युवाओं को ड्रग्स की गिरफ्त से बचाने के लिए आवश्यक निर्देश दी है। कलेक्टर ने कहा कि ÷नशा न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। हमारी प्राथमिकता आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना और युवाओं को इस दलदल से बाहर निकालना है।÷

विभागीय समन्वय से कार्य कर नशे के कारोबार पर अंकुश लगाए-बैठक में कलेक्टर ने पुलिस और आबकारी विभाग को स्पष्ट चेतावनी दी है कि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाए।?कलेक्टर ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए विभागवार समीक्षा की। उन्होंने ?मेडिकल स्टोर्स की सघन जांच: करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देशित की। जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स का नियमित निरीक्षण करने कहा।

शिक्षण संस्थानों के पास निगरानी रखा जाए

बच्चों में नशापन को मिटाने के उद्देश्य से ?शिक्षण संस्थानों के पास निगरानी रखने ,स्कूल और कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ या तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंधित करने निर्देशित की है।

हॉटस्पॉट का चिन्हांकन करने कहा

कलेक्टर ने कहा कि हॉटस्पॉट का चिन्हांकन करने कहा है। उन्होंने पुलिस- विभाग को जिले के उन इलाकों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए जहाँ नशे की गतिविधियां अधिक सक्रिय हैं। ऐसे क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से विशेष निगरानी रखी जाएगी। बैठक में यह चर्चा की गई कि केवल कार्रवाई से नशा खत्म नहीं होगा, इसके लिए सामाजिक जागरूकता जरूरी है। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि प्रार्थना सभाओं और कार्यशालाओं के माध्यम से छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाए। इसी तरह समाज कल्याण विभाग को जिला अस्पताल में नशामुक्ति केंद्र और प्रभावी काउंसलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने कहा कि ÷नशा न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। हमारी प्राथमिकता आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना और युवाओं को इस दलदल से बाहर निकालना है।÷

समन्वय और रिपोर्टिंग

बैठक में पुलिस अधीक्षक (स्क), जिला आबकारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (ष्टस्वाह्व) और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने सभी विभागों को आपसी समन्वय बेहतर करने और हर महीने की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है।

ओवरटाइम व बकाया वेतन को लेकर हंगामा अदाणी पावर प्लांट में श्रमिकों का भारी विरोध

रायगढ़/मूक पत्रिका

जिले में अदाणी पावर प्लांट में मजदूरों ने हल्ला बोल दिया है। सोमवार सुबह से ही पुसौर के बड़े भंडार में अदाणी पावर प्लांट में काम करने वाले कर्मियों और श्रमिकों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में कर्मचारी प्लांट के मुख्य द्वार पर जमा हुए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का मुख्य आरोप है कि उनसे ओवरटाइम काम कराया जा रहा है, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया जा रहा।

कर्मियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से उन्हें समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। आरोप है कि मैनेजमेंट द्वारा तय घंटों से ज्यादा काम लिया जाता है, लेकिन श्ओवरटाइम अलाउंसश् के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा। 12 से 14 घंटे तक काम लिया जा रहा है। कुछ श्रमिकों ने कार्यस्थल पर सुविधाओं की कमी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की बात भी कही है। बड़े भंडार स्थित प्लांट में हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे ताकि स्थिति को नियंत्रित किया। एसडीएम महेश शर्मा ने प्लांट प्रबंधन और कर्मियों की आमने सामने की बात कराई। प्रबंधन द्वारा समय पर वेतन देने की बात सुनकर सैकड़ों श्रमिकों ने वहीं शोर मचाना शुरू कर दिया। प्रशासन द्वारा 25 मार्च तक कंपनी को विवाद को शांत करने की बात पर श्रमिक माने और अपना आंदोलन समाप्त किया। फिलहाल, अदाणी पावर के स्थानीय प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, हालांकि सूत्रों का कहना है कि ठेकेदारों और श्रमिकों के बीच संवाद स्थापित कर मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं श्रमिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनके बकाया वेतन का भुगतान और ओवरटाइम की समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। इससे प्लांट के संचालन पर सीधा असर पडने की संभावना है।

नदी तट की खेती पर रेत माफियाओं का कब्जा, किसानों की रोजी-रोटी छीनी

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

जिले की जीवनदायिनी हसदेव नदी और महानदी के तट पर कभी सैकड़ों एकड़ में फल-सब्जियों की लहलहाती खेती हुआ करती थी, लेकिन अब वही क्षेत्र 'रेत की खेती' का अड्डा बन गया है। रेत माफियाओं की बेलगाम गतिविधियों ने खेती-किसानी करने वाले किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और उन्हें पलायन के लिए मजबूर कर दिया है। करीब डेढ़ दशक पहले तक इन दोनों नदियों के तटीय इलाकों में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी सहित कई मौसमी साग-सब्जियों की भरपूर खेती होती थी। बारिश के बाद जैसे ही नदी का जलस्तर घटता था, किसान नदी तट की रेतीली भूमि पर तंबू गाड़कर फसल उगाते थे। भू-जल स्तर संतुलित रहने के कारण अतिरिक्त सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती थी और चार महीनों में किसान लाखों रुपये की आय अर्जित कर लेते थे। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। तटीय क्षेत्रों में चेन माउंटेन मशीन, जेसीबी और हाईवा-ट्रैक्टरों से बड़े पैमाने पर रेत उत्खनन किया जा रहा है। इसके चलते किसानों के लिए फसल लगाने लायक एक इंच जमीन भी नहीं बची है। खेती छिनने से सैकड़ों परिवारों की आजीविका खत्म हो गई है और कई किसान दूसरे जिलों व राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। कभी जांजगीर-चांपा जिले का तरबूज और खरबूज देशभर में अपनी मिठास के लिए मशहूर था। यहां का तरबूज कोलकाता और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक भेजा जाता था। अब स्थिति यह है कि स्थानीय बाजारों में बाहर से आया फल बिक रहा है। इसका असर कीमतों पर भी पड़ा है–जो तरबूज पहले 50 रुपये में मिल जाता था, वही अब 100 रुपये प्रति नग तक बिक रहा है। ककड़ी और खीरा भी 20 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 50 से 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं शिवरीनारायण क्षेत्र में महानदी पर बनाए गए बैराज ने भी किसानों को खेती से वंचित कर दिया है। बैराज में सालभर पानी भरे रहने से नदी तट की वह रेतीली भूमि समाप्त हो गई, जहां पहले हजारों एकड़ में खेती होती थी। कुल मिलाकर, रेत उत्खनन और जल संरचनाओं के चलते नदी तटों की पारंपरिक खेती लगभग खत्म हो चुकी है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते रेत माफियाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो आने वाले समय में खेती-किसानी पूरी तरह इतिहास बन जाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ेगा।

12 फागिंग मशीन में 5 खराब, नियमित दवा का छिड़काव नही होने से निगम के प्रति लोगो मे नाराज़गी

निगम प्रशासन उदासीनता का शिकार शहर में मच्छरों का बढ़ता प्रकोप जनता दिन रात हो रही परेशान

रायगढ़/मूक पत्रिका

शहर में इन दिनों पूरे 48 वार्ड में मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग दिन और रात दोनों समय मच्छरों से परेशान होकर हलाकान हो रहे हैं। जबकि नगर निगम प्रशासन के पास 7 चालू हालत में फागिंग मशीन यार्ड में हैं और 5 खराब है। वार्ड वासियों के द्वारा सफाई दरोगा को फागिंग से दवा छिड़काव की मांग की जा रही है लेकिन इस दिशा में कोई सुनवाई नही होने से लोगो मे नाराजगी देखने को मिल रहा है। देखा जाएं तो गर्मी शुरू होते ही मच्छरों का प्रकोप आतंक की तरह बढ़ गया है। नालियों की नियमित सफाई नहीं होने और जगह-जगह गंदा पानी जमा रहने से मच्छरों का प्रजनन तेजी से बढ़ रहा है। इन्हें खत्म करने के लिए दवा का छिड़काव भी नहीं हो रहा है। यह इनके प्रकोप को बढ़ाने में काफी मददगार बन रहे है। इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन की ओर से न तो नियमित फॉगिंग कराई जा रही है और न ही दवा का छिड़काव किया जा रहा है। मानो निगम प्रशासन की यह मशीन निगम दफ्तर वाहन शाखा यार्ड की शोभा बढ़ा रही है। लोगों का आरोप है कि कई वार्डों में लंबे समय से फॉगिंग मशीन दिखाई नहीं दी है, जिससे मच्छरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। स्थिति यह है कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। मच्छरों के कारण डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है, जिससे लोगों में चिंता का माहौल है।स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द शहर में व्यापक स्तर पर फॉगिंग कराई जाए, नालियों की सफाई की जाए और एंटी-लार्वा दवा का छिड़काव कराया जाए, ताकि मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से लोगों को राहत मिल सके।

चालू और खराब मशीन बढ़ा रही है यार्ड की शोभा–मच्छरों से राहत दिलाने के नाम पर नगर निगम द्वारा लाखों रुपए खर्च कर फागिंग मशीन की खरीददारी की गई थी। वर्तमान में नगर निगम प्रशासन के बाद 12 फागिंग मशीन है लेकिन इसमें से केवल सात ही चालू है जबकि पांच खराब पड़े हैं उक्त सभी मशीन मानो नगर निगम वाहन विभाग में खड़ी होकर धूल खा रही है।अपुष्ट जानकारी के मुताबिक मशीन का अंदुरुनी समान खराब हो गया है जिस कारण यह सम्भवतः बनने में नाकाम हो सकता है।

शहरी और ग्रामीण दोनो क्षेत्रों के रहवासी हलाकान–विकास का स्वप्न दिखाकर नगर निगम ने अपने अधीन आठ वार्डो को किया था लेकिन इन ग्रामीण वार्डो के रहवासियों को क्या पता था कि यह महज शिगूफा निकलेगा। नए वार्डो का आलम यह है कि गोरखा,भगवानपुर, छातामुड़ा, सराईभद्र, समेत अन्य ग्रामीण वार्डो में सफाई कर्मचारियों द्वारा झांकने तक नही जाते है। स्थानीय लोगो के मुताबिक माह में इक्का दुक्का दिन ही साफ सफाई की खानापूर्ति करते है।

मच्छरदानी और कॉइल बना लोगों का सहारा–शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के बाद लोग बचाव के लिए मच्छरदानी और कॉइल का सहारा लेने को मजबूर हैं। शाम होते ही घरों में मच्छरदानी लगाई जा रही है और कॉइल जलाकर किसी तरह रात काटी जा रही है। इसके बावजूद मच्छरों से पूरी तरह राहत नहीं मिल पा रही है, जिससे लोगों में नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी बढ़ रही है

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।